संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज
समूह संपादक : रवि भारद्वाज
ऊना, शुक्रवार 11 सितंबर 2026 ₹ 2
www.actionindialive.com
Facebook.com/actionindialivee

दिल्ली में एसडीआरएफ के गठन से आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य को मिलेगी गति : रेखा गुप्ता।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
एक्शन इंडिया
वर्ष: 15 अंक: 254 पृष्ठ: 08
RNI : HPHIN/2012/48072
actionindiauna@gmail.com
हिमाचल संस्करण
दिल्ली - हरियाणा - हिमाचल प्रदेश - उत्तराखण्ड - चंडीगढ़
RKB GROUP
Rakesh Bhardwaj Group

सुप्रीम कोर्ट ने पैक्ड फूड में चीनी, नमक और फैट से बच्चों की सेहत पर जताई चिंता, स्पष्ट चेतावनी लेबल जल्द लागू करने के निर्देश

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पैक्ड फूड में चीनी, नमक और वसा की अधिक मात्रा से बच्चों की सेहत पर पड़ रहे बुरे प्रभावों चिंता जताई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट चेतावनी लेबल जल्द लागू करने के लिए एफएसएसएआई को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। एफएसएसएआई ने पैकेट के आगे लाल रंग का चेतावनी निशान लगाने का प्रस्ताव रखा है। कोर्ट इस मामले पर एक-दो दिन के अंदर विस्तृत आदेश जारी करेगा। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है कि वह देश के आम लोगों और खासकर बच्चों की सेहत को लेकर काफी चिंतित है। कोर्ट ने कहा कि देश के स्वास्थ्य से जुड़े इस गंभीर विषय पर सभी संबंधित पक्षों को राष्ट्रीय हित में मिलकर सोचना चाहिए। यह याचिका 3 एस एंड आवर हेल्थ सोसायटी नामक ट्रस्ट ने दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुरकुरे जैसे अत्यधिक प्रोसेस्ड स्नैक्स को अंडे और नमकीन काजू जैसे पौष्टिक खाने के बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शाकाहारी (हरा) और मांसाहारी (लाल) के निशानों से भ्रम न फैले, इसलिए अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड पर चेतावनी के लिए लाल रंग की जगह किसी दूसरे स्पष्ट रंग के निशान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे पहले सुनवाई के दौरान एफएसएसएआई ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि अत्यधिक नमक, चीनी और वसा वाले पैक्ड फूड पर पैकेट के अगले हिस्से में ही लाल रंग का छह कोनों वाला चेतावनी निशान लगाने की योजना है। आईसीएमआर-एनआईएन की 'डायटरी गाइडलाइंस 2024' के आधार पर तय इस निशान पर स्पष्ट रूप से 'हाई फैट', 'हाई शुगर' या 'हाई साल्ट' लिखा होगा, ताकि ग्राहक पैकेट देखते ही पहचान सकें।

आदेश

☐ देश के आम लोगों और खासकर बच्चों की सेहत को लेकर काफी चिंतित है : सुप्रीम कोर्ट

फास्ट न्यूज

हाई कोर्ट ने सीजेपी से कहा- गौरव भाटिया के खिलाफ अपलोड किए गए पोस्ट हटाएं

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) और उसके नेता अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को भाजपा नेता और वकील गौरव भाटिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए पोस्ट को हटाने को कहा है। जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने काकरोच जनता पार्टी के तीनों नेताओं की ओर से पेश वकील से इस संबंध में निर्देश लेकर कोर्ट को बताने को कहा। गौरव भाटिया ने सीजेपी के नेताओं पर दो करोड़ का हजार्ना और उनके खिलाफ किए गए सोशल मीडिया पर पोस्ट पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि सीजेपी और उसके नेताओं ने एआई जनित ग्राफिक्स में स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में गलत तथ्य उनके नाम से जोड़ दिए हैं। भारद्वाज पर सीजेपी कार्यकर्ता के पिता के साथ मारपीट करने का आरोप है। पोस्ट में कहा गया था कि गौरव भाटिया ने स्वतंत्र भारद्वाज को दिमागी नक्सल कहा था। सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ग्राफिक शेयर किया था। गौरव भाटिया ने सौरव दास पर आरोप लगाया कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कोर्ट को लेकर भी अनर्गल पोस्ट करते रहते हैं।
याचिका में कहा गया है कि सौरव दास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की आलोचना की थी और केजरीवाल के मामले की सुनवाई से हटने को कहा था। सौरव दास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद के पक्ष में भी बोला था। ऐसा करना न्यायिक कार्यवाही में दखल देना है।

अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई की मांग खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई की मांग खारिज कर दी है।

रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर सहमति

पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर मर्ज से की बातचीत, रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा

कूटनीतिक

☐ आवाजाही सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बातचीत में व्यापार एवं निवेश, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभाओं की आवाजाही समेत विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बातचीत की जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर दोनों देशों ने व्यापार एवं निवेश, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभाओं की आवाजाही सहित विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। मोदी ने कहा कि जर्मनी के साथ भारत की साझेदारी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच सहयोग को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ाने और दोनों देशों के लोगों के हित में नए अवसर तलाशने पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मनी को यूरोप के साथ भारत के जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए कहा कि वह वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत का एक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी मिलकर अपनी दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए काम करते रहेंगे। दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग आपसी समृद्धि के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर शांति और स्थिरता को मजबूत करने में भी योगदान देगा। उल्लेखनीय है कि भारत और जर्मनी ने वर्ष 1951 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। वर्ष 2026 में दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन उभरती हुई ताकतों को व्यापार, विकास वित्त और पश्चिमी देशों के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के विकल्पों पर पहल को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इस वर्ष भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस नाते भारत 12-13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के नेताओं के साथ-साथ आमंत्रित अतिथियों को भी शामिल किया जाएगा। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में तीन बार इसकी अध्यक्षता कर चुका है।
भारत ने 1 जनवरी 2026 को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की।

चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ब्रिक्स शिखर बैठक के लिए आयेंगे दिल्ली

नई दिल्ली। भारत की अध्यक्षता में हो रहे 18 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12-13 सितंबर को यहां आ रहे हैं। वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने आज यहां सोशल मीडिया पर बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर 12-13 सितंबर को यहां होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
सूत्रों के अनुसार शनिवार तड़के चीनी राष्ट्रपति का विमान यहां पालम तकनीकी हवाईअड्डे पर पहुंचेगा। उनके साथ एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। शनिवार को ही प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। रूस के राष्ट्रपति गुरुवार को देर रात नई दिल्ली पहुंच रहे हैं और शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी वार्षिक शिखर बैठक है। चीन ब्रिक्स का प्रमुख सदस्य देश है। भारत और चीन वैश्विक भू-राजनीतिक बदलावों के बीच बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीलंका के नुवारा एलिया जिले में मौजूद सीता अम्मन मंदिर भी गए।, जहां पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद मांगा।

श्रीलंकाई वायुसेना के लिए एल-70 तोपों के उन्नयन पर समझौता

नई दिल्ली। श्रीलंका की तीन दिवसीय यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दौरे के आखिरी दिन श्रीलंकाई नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय साझेदारी के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करते हुए व्यापक चर्चा की। श्रीलंकाई वायु सेना के लिए एल-70 तोपों के उन्नयन पर समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। साथ ही राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों और राष्ट्रीय कैडेट कोर के बीच शैक्षणिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। इस दौरे में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात में करीबी सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। रक्षा मंत्री एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 08 सितंबर को श्रीलंका की तीन दिवसीय यात्रा पर गए थे। राजनाथ सिंह आज श्रीलंका के नुवारा एलिया जिले में मौजूद सीता अम्मन मंदिर भी गए।,

रेलवे टेंडर घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू, राबड़ी व तेजस्वी पर आरोप तय

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने लालू यादव के दामाद राहुल यादव समेत सात लोगों को बरी करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने इन तीनों के अलावा लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर के खिलाफ आरोप तय किया है। कोर्ट ने राहुल यादव, गौरव गुप्ता, नाथ मल कंकर्निया, विजय त्रिपाठी, डीएन तुलस्यान, राजीव रेलान और अभिषेक फाइनेंस को बरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।कोर्ट ने 28 जनवरी, 2019 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने 19 जनवरी, 2019 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने 13 अक्टूबर, 2025 को रेलवे टेंडर घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

भाजपा ने सातों मोर्चों के बनाए नए प्रभारी

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सात प्रमुख मोर्चों के नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। महासचिव हरीश द्विवेदी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी. पुरंदेश्वरी को भाजपा महिला मोर्चा, राष्ट्रीय महासचिव सतीश पूनिया को अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चा, महासचिव संजय भाटिया को अनुसूचित जाति (एससी) मोर्चा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा को ओबीसी मोर्चा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्या को किसान मोर्चा तथा गजेंद्र पटेल को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा के मुताबिक इन नियुक्तियों से संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच पार्टी की पहुंच को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। हाल के दिनों में पार्टी ने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं।

अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता दें, अल्पकालिक लाभ को नहीं: मोदी

प्रौद्योगिकी

☐ महासागरों और समुदायों तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग हो रहा है : पीएम मोदी

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। अंतरिक्ष में बढ़ती गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को वैश्विक समुदाय से सहयोग, स्थिरता और समावेशन को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में कक्षाएं अधिक भीड़भाड़ वाली, प्रौद्योगिकियां अधिक शक्तिशाली और अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में दुनिया को एकाग्रता के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय स्थिरता और बहिष्कार के बजाय समावेशन का रास्ता चुनना होगा। प्रधानमंत्री ने पेरिस में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत सुरक्षित, संरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना में निहित है। यह भावना अब पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक पहुंचनी चाहिए।
अंतरिक्ष सदियों से मानव की कल्पना को प्रेरित करता रहा है, लेकिन आज इसकी प्रौद्योगिकियां पृथ्वी पर जीवन बचाने में भी मदद कर रही हैं। जलवायु और फसलों की निगरानी से लेकर महासागरों और समुदायों तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग हो रहा है।

दिल्ली में एसडीईआरएफ के गठन की प्रक्रिया शुरू, चर्चा हुई

टीम एक्शन इंडिया

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में राहत एवं बचाव अभियान के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की त्वरित, साहसपूर्ण और समन्वित कार्रवाई के लिए पूरी एनडीआरएफ टीम के प्रति दिल्लीवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में दिल्ली के लिए एक सशक्त और आधुनिक स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स (एसडीईआरएफ) के गठन पर विस्तार से चर्चा हुई।

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त के रूप में 10.10 लाख बहनों के खातों में 212.16 करोड़ रुपये की राशि जारी

सैनी ने 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1,890 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की

डबल इंजन सरकार

☐ उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की 7 योजनाओं के तहत लाभार्थियों को 311.25 करोड़ रुपये की राशि जारी

टीम एक्शन इंडिया

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत 50 लाख 28 हजार 208 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 1 हजार 890 करोड़ 16 लाख रुपये की राशि जारी की। इनमें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त, बुजुर्गों व दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जरूरतमंद परिवारों को दयालु योजना की आर्थिक सहायता, गृहिणियों को गैस सब्सिडी, किसानों को भावांतर भरपाई शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार का संकल्प है कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ सीधे, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को हरियाणा निवास में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी' योजना की 11वीं किस्त जारी की गई है। इसके तहत 10 लाख 10 हजार लाभार्थी बहन-बेटियों के खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपये डाले गए हैं। इसके साथ ही योजना के तहत अब तक 11 किस्तों में 2 हजार 254 करोड़ 47 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आगामी 17 सितंबर से 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 6 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव के. मकरंद पांडुरंग, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक डॉ. आदित्य दहिया तथा अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) विवेक कालिया, मनीष लोहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1,129 करोड़ रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 6 हजार 841 लाभार्थियों के खातों में 1 हजार 129 करोड़ 5 लाख रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं।

10 सितंबर 2026
हरियाणा निवास संक
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा
Disbursal of Incentives to Beneficiaries Under Various Schemes
Shri Nayab Singh Saini
Hon'ble Chief Minister, Haryana
Shri Rao Narbir Singh
Hon'ble Minister of Industries & Commerce, Haryana
10th September 2026

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित करते हुए। (10.09.2026)

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम में ली गौ सेवकों एवं अधिकारियों की बैठक

दिशा-निर्देश

☐ पशु संरक्षण एवं उपचार व्यवस्था को बेहतर बनाने गौ सेवकों से लिए सुझाव आदि को लेकर दिए निर्देश

टीम एक्शन इंडिया

रायपुरः उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिला कार्यालय के सभाकक्ष में गौ सेवकों एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में सड़क पर विचरण करने वाले पशुओं, बीमार एवं घायल पशुओं के रेस्क्यु, उपचार तथा उनके लिए व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने गौ सेवकों से उनके कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं की जानकारी ली और पशुओं के बेहतर संरक्षण एवं उपचार के लिए आवश्यक सुझाव भी लिए। बैठक में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेषर पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर नरेन्द्र पैकरा, गौ सेवक नीलेश सोनी, संस्कार दुबे, तरूण साहू, अंकुश विश्वकर्मा, अनमोल ठाकुर, वैदिक मिश्रा, नीरज ठाकुर, अमित चंद्रवंशी सहित जनप्रतिनिधि, गौ सेवक उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गौ सेवक दिन-रात बीमार और घायल पशुओं की सेवा में जुटे रहते हैं। वे पूरी मेहनत, लगन और सेवाभाव के साथ सड़क पर घायल अवस्था में मिले पशुओं का रेस्क्यु कर उन्हें उपचार के लिए पशु चिकित्सालय तक पहुंचाते हैं।

सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में एक बार फिर शाहजहांपुर अव्वल, रामपुर को मिला दूसरा स्थान

☐ जनशिकायतों के निस्तारण में मारी बाजी, फीड बैक में भी रहा अव्वल, अगस्त की रैंकिंग में रामपुर दूसरे व बरेली तीसरे स्थान पर, जन समस्याओं के प्रति सीएम योगी की गंभीरता का दिख रहा असर, प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा निस्तारण, जन समस्याओं के प्रति सीएम योगी की गंभीरता का दिख रहा असर, प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा निस्तारण

कार्यप्रणाली

☐ प्रभावी निस्तारण, फीडबैक और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधारात्मक पहल से हासिल किया है: जिलाधिकारी

टीम एक्शन इंडिया
लखनऊ: योगी सरकार द्वारा पिछले साढ़े नौ वर्षों से प्रदेश में सुशासन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर धरातल पर साफ देखा जा सकता है। सीएम डैशबोर्ड की अगस्त की रैंकिंग में एक बार फिर शाहजहांपुर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं, रामपुर ने दूसरा और बरेली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। रामपुर, शाहजहांपुर और बरेली के जिलाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने यह उपलब्धि जनशिकायतों के प्रभावी निस्तारण, बेहतर फीडबैक और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधारात्मक पहल से हासिल किया है।

शाहजहांपुर ने 9.53 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त कियाॅ

शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट उन जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जिन्होंने प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों और राजस्व प्रबंधन में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप शाहजहांपुर में विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम डैशबोर्ड के जरिये मिलने वाली शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सीएम डैशबोर्ड की अगस्त माह की रैंकिंग में शाहजहांपुर को 10 में से 9.53 अंक प्राप्त हुए। इसी के साथ शाहजहांपुर ने प्रदेशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है।

वहीं रामपुर ने 9.48 अंक हासिल कर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

रामपुर ने 10 में से 9.48 अंक प्राप्त कर बाजी मारी, टॉप टेन जिलों में आजमगढ़, पीलीभीत और मैनपुरी ने स्थान प्राप्त किया

रामपुर डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जिलों का मूल्यांकन कई मानकों के आधार पर किया जाता है। इसमें जनशिकायतों का समयबद्ध निस्तारण, प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई, फीडबैक की गुणवत्ता और योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे पहलू शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई में सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से जिले की 68 योजनाओं की मॉनीटरिंग की गई। इसमें से 65 कार्यक्रमों में जिले ने ए ग्रेड प्राप्त किया। जिले ने वैकल्पिक ऊर्जा, ऊर्जा, कृषि विभाग, समाज कल्याण, लोक निर्माण विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, मत्स्य विभाग, उद्योग विभाग, सहकारिता एवं सिंचाई के कार्यक्रमों में शत-प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए ए श्रेणी प्राप्त की है। सीएम डैशबोर्ड की अगस्त की रैंकिंग में रामपुर को 10 में से 9.48 अंक प्राप्त हुए। इसी के साथ एक बार फिर रामपुर ने सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा रामपुर पिछले कई माह से सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में टॉप टेन में जिलों में बना हुआ है। वहीं बरेली ने 9.43 अंक हासिल कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

टॉप टेन जिलों में आजमगढ़, पीलीभीत और मैनपुरी ने स्थान प्राप्त किया

सीएम डैशबोर्ड की अगस्त माह की रैंकिंग में कई जिलों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। इसमें आजमगढ़ और पीलीभीत ने बराबर-बराबर 9.36 अंक हासिल कर चौथा, मैनपुरी ने 9.34 अंक हासिल कर पांचवा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह महराजगंज ने 9.27 अंक प्राप्त कर छठवां, अंबेडकरनगर ने 9.26 अंक प्राप्त कर सातवां, सुल्तानपुर ने 9.24 अंक प्राप्त कर आठवां, हरदोई ने 9.23 अंक प्राप्त कर नौवां और सोनभद्र ने 9.21 अंक प्राप्त कर टॉप टेन में जगह बनायी है।

बाढ़ पीड़ितों को एक्सपायर्ड सीरप बांटने का आरोप तथ्यहीन

टीम एक्शन इंडिया
कानपुर: बाढ़ पीड़ितों को एक्सपायर्ड सीरप बांटे जाने के आरोपों को कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन्द्रदेव सिंह ने तथ्यहीन बताया है। जांच के बाद सीएमओ ने स्पष्ट किया कि 02 सितंबर को आयोजित बाढ़ राहत कैम्प में ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथॉक्साजोल आईपी सीरप का वितरण नहीं किया गया था। उन्होंने संबंधित खबर का खंडन करते हुए विभागीय रिकॉर्ड और दवा के स्टॉक की स्थिति को आरोपों के विपरीत बताया। रिकॉर्ड के मुताबिक उक्त सीरप वर्ष 2025 में ड्रग वेयरहाउस कानपुर नगर में प्राप्त हुआ था। इसके बाद मार्च 2025 तक सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सीरप वितरित किया जा चुका था। वर्तमान में किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उक्त बैच की दवा उपलब्ध नहीं है। जांच के दौरान बाढ़ राहत के लिए बनाए गए स्टॉक रजिस्टर को भी देखा गया। रजिस्टर में ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथॉक्साजोल आईपी सीरप की एक भी प्रविष्टि नहीं मिली। ऐसे में 02 सितंबर को बाढ़ कैंप में उक्त सीरप बांटे जाने की बात विभागीय रिकॉर्ड से पुष्ट नहीं

भारथक्लाउड और आइबेंटोस की साझेदारी, एआई से बदलेगी ब्रांड मार्केटिंग और इवेंट टेक्नोलॉजी

इनोवेशन

☐ भारथक्लाउड के साथ हमारा विजन और इनोवेशन को लेकर नजरिया मिलता-जुलता है

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली: भारत की सॉवरेन एआई क्लाउड प्रदाता कंपनी भारथक्लाउड ने एआई-आधारित टेक्नोलॉजी कंपनी आइबेंटोस के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत और कनाडा में एआई-संचालित ब्रांड मार्केटिंग और इवेंट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है। यह समझौता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित सातवें भारत-कनाडा व्यापार एवं निवेश मंत्रिस्तरीय संवाद के दौरान हुए भारत-कनाडा बिजनेस समिट में हुई चर्चा के बाद औपचारिक रूप से किया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 में बढ़कर 23.66 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें वस्तु व्यापार में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।इस साझेदारी के तहत भारथक्लाउड अपने मार्केटिंग अभियानों को तैयार करने और प्रबंधित करने के लिए आइबेंटोस के नए एआई-प्लेटफॉर्म 'आइबेंटोस हाइप' का उपयोग करेगी। साथ ही कंपनी अपने ग्राहकों को भी यही एआई-आधारित मार्केटिंग क्षमताएं उपलब्ध कराने पर काम करेगी। दोनों कंपनियां मिलकर एआई-आधारित इवेंट अनुभवों को और बेहतर बनाने पर भी फोकस करेंगी। भारथक्लाउड के सह-संस्थापक राहुल तक्कल्लापल्ली ने कहा, ₹भारत-कनाडा मिशन के दौरान आइबेंटोस टीम से बातचीत में नवाचार को लेकर साझा दृष्टिकोण दिखा। हमें ऐसा टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए था जो मार्केटिंग और इवेंट में स्मार्ट अनुभव ला सके। वहीं आइबेंटोस इंक. के सह-संस्थापक और सीएमओ जसपिंदर भाटिया ने कहा, भारथक्लाउड के साथ हमारा विजन और इनोवेशन को लेकर नजरिया मिलता-जुलता है। हमारा एक दशक का अनुभव और हाइप प्लेटफॉर्म मिलकर ब्रांड्स को स्केलेबल मार्केटिंग समाधान देगा।

डीएफएस सचिव ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए नवाचारों का अनावरण किया

टीम एक्शन इंडिया
शिमला: वित्त मंत्रालय,भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया ने आज देश में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में कई नवाचारों का शुभारंभ किया। इन पहलों में तत्काल रुपे कार्ड और मर्चेंट यूपीआई क्यूआर जारी करने के लिए ओपन सोर्स (एंड्रॉयड) एटीएम की शुरूआत, चुनिंदा सरकार समर्थित ऋण योजनाओं के लिए यूपीआई पर क्रेडिट लाइन की सुविधा तथा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के तहत थ्री पार्टी कैश डिपॉजिट की शुरूआत शामिल है। रुपे कार्ड और मर्चेंट क्यूआर जारी करने के लिए ओपन सोर्स एटीएम,यह समाधान ग्राहकों को एक सरल सेल्फ सर्विस प्रक्रिया के माध्यम से एटीएम से सीधे तत्काल व्यक्तिगत रुपे डेबिट,क्रेडिट और एनसीएमसी कार्ड प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ओपनसोर्स एटीएम यूपीआई आधारित भुगतान स्वीकार करने के लिए मर्चेंट क्यूआर कोड भी जारी करेगा जिससे व्यापारी आसानी से क्यूआर कोड स्थापित कर सकेंगे और भुगतान स्वीकार करना शुरू कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त ये एटीएम चेक जमा करने,खाता खोलने और ऋण के लिए आवेदन करने जैसी बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगे।इस समाधान का उद्देश्य एटीएम की भूमिका को केवल नकद निकासी और जमा करने वाली मशीनों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें स्मार्ट ग्राहक सेवा और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के केंद्र के रूप में विकसित करना है।

दिल्ली में 13-20 सितंबर तक 30वां विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन : संत राजिन्दर सिंह

कार्यशालाएं

☐ आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान-अभ्यास की कार्यशालाएं और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएंगे

टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली: सावन कृपाल रूहानी मिशन के प्रमुख संत राजिन्दर सिंह जी महाराज के मार्गदर्शन और उनकी दिव्य उपस्थिति में दिल्ली में 13 से 20 सितंबर, 2026 तक 30वां विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस साल यह सम्मेलन खास महत्व रखता है क्योंकि इस अवसर पर संत राजिन्दर सिंह जी महाराज का 80वां जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा, जो उनके दिव्य-प्रेम, करुणा, आध्यात्मिकता और मानव एकता के संदेश के आठ दशकों का प्रतीक है। यह वार्षिक सम्मेलन दुनिया भर के आध्यात्मिक नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों को एक साथ बैठने का मौका देता है - जिनमें अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कनाडा और पूरे भारत के लोग शामिल हैं - ताकि वे इस बात पर आपस में अपने विचार साझा कर सकें कि आध्यात्मिकता और ध्यान-अभ्यास समाज में आंतरिक शांति, करुणा और सद्भाव की भावना जगाने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सम्मेलन विभिन्न आध्यात्मिक नेताओं को मानव एकता पर विचार करने और प्रेम और करुणा का संदेश साझा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अन्य विशिष्ट अतिथियों के साथ इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगी। आठ दिनों के इस कार्यक्रम में कृपाल बाग और दिल्ली के बुराड़ी में स्थित संत दर्शन सिंह जी धाम (19-20 सितंबर) में आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान-अभ्यास की कार्यशालाएं और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएंगे।

आरबीआई के उप गवर्नर ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में भारत कनेक्ट पर विदेशी मुद्रा सेवाओं के लिए मल्टी करेंसी क्षमताओं की शुरूआत की

टीम एक्शन इंडिया
शिमला: आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रोहित जैन ने आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में भारत कनेक्ट पर फॉरेक्स कैटेगरी के लिए मल्टी करेंसी क्षमताओं की शुरूआत की घोषणा की।यह पहल फिलहाल सॉफ्ट लॉन्च के रूप में की जा रही है। टेस्टिंग चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने और उसके आकलन के बाद इस सुविधा को भारत कनेक्ट के अधिक चैनलों और भागीदार बैंकों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।यह प्लेटफॉर्म एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) द्वारा संचालित है और क्लियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित एफएक्स रिटेल के साथ एकीकृत है। क्लियरकॉर्प,द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।अब यह प्लेटफॉर्म यूरो,ब्रिटिश पाउंड,कनाडाई डॉलर,स्विस फ्रैंक, यूएई दिरहम को सपोर्ट करेगा। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा फॉरेक्स सुविधा को अमेरिकी डॉलर से आगे बढ़ाना और ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉरेक्स सेवाओं की व्यापक रेंज तक पहुंच उपलब्ध कराना है।

सीएम की संवेदनशील पहल- शशिकांत को एम्स रायपुर में कराया भर्ती

टीम एक्शन इंडिया
रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल से धमतरी जिले के ग्राम देवपुर निवासी 29 वर्षीय शशिकांत भरत को बेहतर इलाज की नई उम्मीद मिली है। सोशल मीडिया के माध्यम से शशिकांत की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और उनसे दूरभाष पर बात कर कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शशिकांत को 9 सितंबर की शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (अक्क्ष्टर), रायपुर में भर्ती कराया, जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उनके उपचार के लिए 4 लाख रुपये की सहायता राशि भी स्वीकृत की है।

2016 में हुए हादसे के बाद से प्रभावित है स्वास्थ्य

वर्ष 2016 में एक सड़क दुर्घटना के दौरान शशिकांत को गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण वे करीब 50 दिनों तक कोमा में रहे। दुर्घटना में सर्वाइकल की समस्या उत्पन्न होने से उनके हाथ-पांव की कार्यक्षमता प्रभावित हो गई थी। लंबे समय तक विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो पाया था।

शशिकांत ने जताया आभार

मुख्यमंत्री से बातचीत और तुरंत मिली चिकित्सकीय सहायता के बाद शशिकांत ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं फोन कर हाल-चाल पूछना और एम्स में इलाज के साथ 4 लाख रुपये की सहायता देना उनके और उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा संबल है।

उद्यमी आयोग के सदस्य ने सीएम से की मुलाकात, अररिया सहित सीमांचल के समस्याओं के निराकरण पर की चर्चा

टीम एक्शन इंडिया
अररिया: बिहार राज्य उद्यमी आयोग के सदस्य एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक भगत उर्फ बमशंकर भगत ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पटना में गुरुवार को मुलाकात कर अररिया सहित सीमांचल से जुड़े उद्योग धंधे सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की और उसके निराकरण को लेकर सकारात्मक प्रयास करने की विनती की। जानकारी देते हुए श्री भगत ने बताया कि सीमांचल में उद्योग धंधे स्थापित करने खासकर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग स्थापित करने,किसानों की समस्याओं के तहत सरकारी रेट पर यूरिया और डीएपी उपलब्धता पर चर्चा की।साथ ही नरपतगंज बाजार में फोरलेन सड़क पर अंडर पास में होने वाले जलजमाव की समस्या पर निराकरण के लिए एनएचएआई से पहल करने की मांग की।इसके अलावा बॉर्डर सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रकोप और तस्करी जैसे मुद्दों पर भी विशेष चर्चा की गई।

चर्चा

☐ किसानों की समस्याओं के तहत सरकारी रेट पर यूरिया और डीएपी उपलब्धता पर चर्चा की

श्री भगत ने सीएम को बताया कि अररिया और सीमांचल में उद्योग धंधों की अपार संभावनाएं हैं।

खासकर जिस तरह से कुछ वर्षों में मक्का के उत्पादन और किसानी को लेकर किसानों का रुझान बढ़ा है। मक्का आधारित उद्योग धंधे स्थापित होने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा।वहीं बंद पड़े और बंद के राह पर स्थापित उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए निवेशकों और उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर भी उद्यमी आयोग के सदस्य ने ध्यान आकृष्ट कराया।

रायबरेली में कांग्रेस नेता के बयान पर योगी सरकार के मंत्री ने किया करारा पलटवार

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी पवित्र योजना पर राहुल का सवाल उठाना मातृशक्ति का अपमान: दिनेश

साधा निशाना

☐ योगी सरकार की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा, सम्मान और विकास है, विपक्ष को निभानी चाहिए रचनात्मक भूमिका

टीम एक्शन इंडिया
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता एवं रायबरेली के सांसद राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि रायबरेली की दिशा बैठक में राहुल गांधी का जोर जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें गति देने के बजाय बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं में खामियां तलाश कर राजनीति करने पर अधिक रहा। मंत्री ने कहा कि बैठक में राहुल गांधी के रवैये से निराशा हुई।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर सवाल उठाने का आरोप

राज्यमंत्री ने कहा कि दिशा बैठक में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने संबंधित अधिकारी से पूछा कि इस योजना में क्या होता है। यदि दिशा समिति के अध्यक्ष को ही योजना की जानकारी नहीं होगी तो उसका अनुश्रवण और समन्वय कैसे होगा। इसके बाद राहुल गांधी ने योजना के प्रचार-प्रसार पर होने वाले खर्च को जानने पर अधिक जोर दिया। इससे ऐसा लगा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के बजाय उसमें खामी तलाशना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बेटियों और मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा अभियान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है।

डरो मत कहने वाले राहुल गांधी जनता और मीडिया से क्यों बच रहे? दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के डरो मत संदेश पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि रायबरेली में उन्होंने सांसद निधि से कराए गए कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास अपने निजी आवास के भीतर से किया, जबकि बाहर के गेट पर ताला लगा रहा। मीडिया प्रतिनिधि सुबह से इंतजार करते रहे, लेकिन राहुल गांधी कैमरे के सामने आकर रायबरेली की जनता को शुभकामनाएं तक नहीं दे सके।

राहुल को तीन लोग पीछे बैठकर पर्चियों के माध्यम से निर्देश देते रहे

२राज्यमंत्री ने कटाक्ष किया कि रायबरेली की दिशा बैठक में भी राहुल गांधी सांसद और समिति अध्यक्ष से ज्यादा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आए। उनके साथ दिल्ली से आए तीन लोग पीछे बैठकर पर्चियों के माध्यम से निर्देश देते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में भी राहुल गांधी दूसरे दलों के सहयोग पर निर्भर दिखाई देते हैं।

योगी सरकार में सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि

राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में जनता की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नीति के साथ काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की सराहना देश के साथ विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों द्वारा भी की गई है।

अखिलेश के बुलंदशहर दौरे पर बोले- सरकार ने किसी को नहीं रोका

अखिलेश यादव के बुलंदशहर दौरे में हेलीपैड की अनुमति से जुड़े सवाल पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलना किसी राजनीतिक भय का विषय नहीं है।

सीबीएसई स्कूलों के लिए ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म और भवन रंग योजना तय

शिक्षा

» विद्यार्थियों को घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : सीएम

टीम एक्शन इंडिया
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां शिक्षा विभाग की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड, विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म तथा स्कूल भवनों के लिए रंग योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में चर्चा की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सीबीएसई स्कूलों के विद्यार्थियों की विशिष्ट यूनिफॉर्म हरे रंग की थीम पर आधारित होगी। इन स्कूलों की महिला शिक्षिकाएं हल्के लाइलैक (बैंगनी) रंग की पोशाक पहनेंगी, जबकि पुरुष शिक्षक हल्के नीले रंग की पैंट और शर्ट पहनेंगे। इन स्कूलों के भवनों को ऑलिव ग्रीन और सैंड बेज रंगों से रंगा जाएगा। शिक्षकों का ड्रेस कोड साफ-सुथरा, औपचारिक, शालीन और पेशेवर होगा तथा इसमें न्यूनतम सहायक वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा। डयूटी के दौरान शिक्षकों को अपना पहचान पत्र पहनना भी अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को उनके घरों के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार ने सीबीएसई स्कूलों में आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 80 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए जाएंगे। बैठक में विधायक सुरेश कुमार, चंद्र शेखर और नीरज नैय्यर, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के सदस्य विजय पाल सिंह, सचिव शिक्षा राकेश कंवर, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

संदेश-कांग्रेस सरकार जाने वाली है, भाजपा सरकार आने वाली है : डॉ. राजीव बिंदल

टीम एक्शन इंडिया
शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस विजय ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार से मोहभंग हो चुका है।

प्रदेश में राजनीतिक वातावरण तेजी से बदल रहा है और जनता ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। डॉ. बिंदल ने कहा कि जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी।

न सत्ता का दुरुपयोग काम आया, न साजिशें, लोकतंत्र जीता, तानाशाही हारी : जयराम ठाकुर

सम्मान

» इस हार से सबक ले संविधान, लोकतंत्र और जनादेश का सम्मान करना सीखें मुख्यमंत्री

टीम एक्शन इंडिया
शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर भूपेंद्र सिंह सिसोदिया और उपाध्यक्ष के पद पर भारत सिंह कलांटा की जीत पर बधाई दी। शिमला से जारी बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जमकर घेरा।

जयराम ठाकुर ने कहा कि न तो मुख्यमंत्री के सत्ता का दुरुपयोग और हथकंडे काम आए और न ही उनकी एक भी साजिश कामयाब हुई। बस मुख्यमंत्री का संविधान और लोकतंत्र विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है, तानाशाही हारी है। मुख्यमंत्री को पंचायत चुनाव में कदम दर कदम मिली हार से सबक लेना चाहिए। वह न सिर्फ जनता की अदालत में हारे, बल्कि अपने संविधान विरोधी तानाशाही फैसलों की वजह से न्यायालय में भी मुंह की खाए। उन्हें इस हार से यह समझ लेना चाहिए कि व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान के हिसाब से चलेगी, उनकी तानाशाही और तुगलकशाही के हिसाब से नहीं।

मुख्यमंत्री के पास अब जितनी भी ऊर्जा और समय बचा है, वह मनमानी के नियम बनाकर कानूनी लड़ाई में लगाकर मुंह की खाने के बजाय प्रदेश हित में लगाएं। सिर्फ पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव में ही मुख्यमंत्री एक दर्जन से

ज्यादा बार न्यायालय में सरकार की फजीहत करवा चुके हैं। आज शिमला जिला परिषद के चुनाव भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई तारीख पर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का बस चलता तो यह चुनाव न जाने कब करवाते।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू सत्ता का सेमीफाइनल बुरी तरह हार चुके हैं। पंचायती चुनाव का जनादेश कांग्रेस के सिर्फ खिलाफ नहीं गया, बल्कि कांग्रेस को साफ कर गया है।

दूसरी बार संसद रत्न सम्मान मिलने पर भाजपा नेताओं ने अनुराग सिंह ठाकुर को दी बधाई

पवन धीमान
हमीरपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को दूसरी बार प्रतिष्ठित संसद रत्न सम्मान प्राप्त करने पर बधाई दी है। भाजपा नेताओं ने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी उत्कृष्ट संसदीय कार्यशैली, प्रभावी भागीदारी और जनहित से जुड़े विषयों को संसद में मजबूती से उठाकर न केवल हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है।

जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और आशीष शर्मा, वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक

राजिंदर सिंह राणा, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, डॉ. अनिल धीमान और कमलेश कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष अनीता देवी सहित पार्टी पदाधिकारियों अजय रिंटू शर्मा, अजमेर ठाकुर, देशराज शर्मा, हरीश शर्मा, विनोद ठाकुर छंब, राजकुमारी ठाकुर तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुराग सिंह ठाकुर को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं।

गौरतलब है कि संसद रत्न सम्मान की विशेषता यह है कि यह सामान्य पुरस्कारों की तरह केवल नामांकन आधारित सम्मान नहीं है, बल्कि संसद में सांसदों और संसदीय समितियों के प्रदर्शन से जुड़े तथ्यात्मक एवं निर्धारित मानकों के आधार पर प्रदान किया जाता है।

इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2010 में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर हुई थी। इसका उद्देश्य संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करना है।

चुराह में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक संपन्न, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प

हामिद खान
चंबा। लोक निर्माण विभाग रेस्ट हाउस, कॉलोनी मोड़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुराह की ओर से संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी संगठनात्मक रणनीतियों और बूथ स्तर पर पार्टी को धार देने को लेकर गंभीर मंथन किया गया। बैठक में चुराह विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी करतार ठाकुर और सह-प्रभारी हसन दीन विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा चुराह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशवंत सिंह खन्ना की विशेष मौजूदगी ने कार्यक्रम के महत्व को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के विभिन्न नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके आधिकारिक उत्तरदायित्व पत्र सौंपे, जिससे कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिला। बैठक के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन का जड़ से मजबूत होना अनिवार्य है। चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना और अधिक से अधिक आम जनता को संगठन के साथ जोड़ना रहा। नेताओं ने स्पष्ट किया कि केवल कागजी कार्रवाई से संगठन नहीं चलता, बल्कि हर एक कार्यकर्ता को मैदान में उतरकर पार्टी की नीतियों को घर-घर पहुंचाना होगा।

संक्षिप्त खबरें

चम्बा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से होगा

हामिद खान
चंबा। जिला चम्बा सहित पूरे देश में आगामी 12 सितंबर, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों और प्री-लिटिगेशन (वाद-पूर्व) स्तर के मुकदमों का आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण माहौल में त्वरित समाधान करना है।

प्राधिकरण ने आम जनमानस से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं। लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों के निस्तारण से न केवल लंबे समय से चल रहे विवादों का अंत होता है, बल्कि समय और धन की भी महत्वपूर्ण बचत होती है। लोक अदालत में जिन मामलों का निपटारा किया जाएगा उनमें

आपराधिक और शमनीय अपराधों से जुड़े मामले एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामले ,बैंक ऋण वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद और बिजली-पानी के बिलों से संबंधित मामले, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद ,?भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना दावा और अन्य सिविल वाद शामिल रहेंगे। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, मीडिया कर्मियों और सामाजिक संगठनों से आग्रह किया है कि वे इस संदेश को अधिक से अधिक साझा करें ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंच सके और वह इस किफायती एवं सुलभ न्याय प्रणाली का हिस्सा बन सके।

22वें दिन भी जारी रही भूख हड़ताल, एबीवीपी ने एचपीटीयू में की तालाबंदी

पवन धीमान
हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (एचपीटीयू) में विद्यार्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की भूख हड़ताल 22वें दिन भी जारी रही। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मांगों पर ठोस पहल न होने से आक्रोशित परिषद कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विश्वविद्यालय में तालाबंदी कर विरोध दर्ज करवाया।

एबीवीपी विभाग संयोजक भवानी ठाकुर ने कहा कि परिषद की प्रमुख मांगों में विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति, सेल्फ फाइनेंस मॉडल पर चल रहे विश्वविद्यालय को पर्याप्त सरकारी वित्तीय सहयोग तथा कैंपस की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान शामिल है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लगातार प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में गांधी चौक हमीरपुर में आयोजित छात्र रैली में करीब 2500 विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की थी। इसके बावजूद सरकार की ओर से अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई। भवानी ठाकुर ने कहा कि 22 दिनों से विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि विद्यार्थियों से वार्ता करने नहीं पहुंचा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी आंदोलनरत विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल नहीं की गई।

उन्होंने कहा कि संवाद के प्रयासों के बावजूद जब विद्यार्थियों की मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो परिषद को तालाबंदी का कदम उठाना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिषद टकराव नहीं चाहती, लेकिन विद्यार्थियों की मांगों को लगातार नजरअंदाज किए जाने की स्थिति में आंदोलन तेज करना मजबूरी बन गया है।

एबीवीपी ने सरकार से मांग की कि वह तत्काल विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करे और उनकी मांगों के समाधान के लिए ठोस निर्णय ले। परिषद ने कहा कि आंदोलन किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि तकनीकी शिक्षा और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर है।

18 को हमीरपुर में 1,31,000 बच्चों एवं नवयुवाओं को दी जाएगी कृमिनाशक दवा

पवन धीमान
हमीरपुर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत 18 सितंबर को जिला हमीरपुर के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और शिक्षण संस्थानों में एक से 19 साल तक के सभी बच्चों, किशोरों और नवयुवाओं, जिनकी संख्या लगभग 1,31,000 है, को कृमिनाशक दवाई एल्बेंडाजोल दी जाएगी। इनमें एक से 5 वर्ष तक के 27,419 बच्चों को विटामिन-ए की खुराक भी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रमों की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी अभिषेक गर्ग ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बच्चे के पेट में कृमि होने पर उसका शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है और वह अनीमिया जैसी बीमारी की चपेट में भी आ सकता है। इसलिए, 19 वर्ष तक के हर बच्चे एवं युवा के लिए कृमिनाशक दवाई बहुत ही जरूरी है। बच्चों में आंखों की समस्याओं के निवारण के लिए विटामिन-ए दवाई बहुत जरूरी है।

उन्होंने कहा कि सभी आशा एवं आंगनवाड़ी वर्कर्स और शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारी एवं प्रभारी शिक्षक बच्चों को अपनी उपस्थिति में ही यह दवाई खिलाना सुनिश्चित करें। कोई भी बच्चा इससे छूटना नहीं चाहिए। किन्हीं कारणों से छूटे बच्चों को 25 सितंबर को यह दवाई दी जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के अन्य प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए एडीसी ने कहा कि जिला में 14-15 वर्ष के आयु वर्ग की 1947 यानि लगभग 66 प्रतिशत लड़कियों को सर्विकल कैंसर रोधी टीका लगाया जा चुका है। इससे छूटी लड़कियों के टीकाकरण के लिए स्कूल स्तर पर अभियान चलाया गया है। शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारी एवं शिक्षक इस आयु वर्ग की सभी लड़कियों के टीकाकरण के लिए सक्रिय योगदान दें। अभिषेक गर्ग ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग छोटे बच्चों को अलग-अलग समय पर विभिन्न वैक्सीनों की कुल 27 खुराकें निशुल्क प्रदान कर रहा है। ये वैक्सीन बच्चों को 12 बीमारियों से बचाती हैं। इसी तरह एचपीवी का टीका लड़कियों को भविष्य में सर्विकल कैंसर से बचाएगा।

एडीसी ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की। बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने कृमि मुक्ति दिवस, एचपीवी और अन्य प्रतिरक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सभी बीएमओ, शिक्षा और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

12 में से 11 जिला परिषदों में भाजपा का परचम, इससे बड़ा राजनीतिक संकेत और क्या होगा : हर्ष महाजन

चमन शर्मा
शिमला। शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 26 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जिला परिषद के दोनों शीर्ष पदों पर भाजपा का परचम लहरा दिया। चंदलोग-नेरूवा वार्ड से निर्वाचित भूपेंद्र सिंह सिसोदिया अध्यक्ष तथा टिक्कर वार्ड से निर्वाचित भरत सिंह कलांटा उपाध्यक्ष चुने गए।

अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा समर्थित भूपेंद्र सिंह सिसोदिया को 13 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस समर्थित सुरेंद्र रेटका को 10 मत मिले और दो मत निरस्त हुए। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा समर्थित भरत सिंह कलांटा को 14 मत मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित मीनाक्षी को 10 मत प्राप्त हुए और एक मत निरस्त हुआ।

भाजपा ने इस जीत को केवल जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश में बदलते राजनीतिक माहौल और कांग्रेस सरकार के प्रति बढ़ते जनाक्रोश का स्पष्ट संकेत बताया है।

चुनाव परिणाम घोषित होते ही शिमला में भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्वागत किया तथा एक-दूसरे को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी।

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने भाजपा की शानदार जीत पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सिसोदिया और उपाध्यक्ष भरत सिंह कलांटा सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिला परिषदों के परिणाम प्रदेश की राजनीतिक दिशा का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, प्रदेश की 12 जिला परिषदों में से 11 में भाजपा का प्रभाव स्थापित होना अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। इससे ज्यादा और क्या संकेत चाहिए कि हिमाचल की जनता किसके साथ खड़ी है।

महाजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में ऐसा वातावरण बना दिया है जहां राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एफआईआर

और पुलिस-प्रशासन के इस्तेमाल के आरोप लगातार लग रहे हैं। कर्मचारी परेशान हैं, नौजवान रोजगार को लेकर निराश हैं, महिलाएं परेशान हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का कितना भी प्रयास कर ले, अब प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है।

किन्नौर मे नोतोड़ के विषय को लेकर प्रदेश के राज्यपाल नहीं गंभीर : जगत सिंह नेगी

अनिल नेगी
रिकांगपिओ। ज़िला किन्नौर के रिकांगपिओ मे वीरवार को प्रदेश के केबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने मिडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ज़िला किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है जहाँ बीते कई वर्षो से लोगों को कृषि हेतू भूमि की भारी कमी है। ऐसे मे जब जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई तब तब लोगों को नोतोड़ के तहत भूमि देने का काम कर रही है।लेकिन वर्तमान मे प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नोतोड़ के तहत भूमि नहीं मिल रही और हजारों लोगों के नोतोड़ के तहत मिलने वाली भूमि व उनके फ़ाइल सरकारी कार्यालयों मे धूल फांक रहे है।उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार जनजातीय लोगों को

नोतोड़ के तहत भूमि देने हेतू लगातार प्रयासरत है लेकिन प्रदेश के राज्य पाल एफसीए 1980 को निरस्त नहीं कर रहे जिसकारण नोतोड़ की प्रक्रिया रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं कई बार राज्यपाल से नोतोड़ के संदर्भ मे मुलाक़ात की परन्तु पूर्व व वर्तमान राज्य पाल का नोतोड़ के प्रति सही संकेत नहीं मिले न ही एफसीए 1980 को निरस्त किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान सरकार नोतोड़ व एफआरए पर काम कर रही है।और वर्ष 2014 से 2018 तक कांग्रेस की सरकार के समय नोतोड़ भूमि प्रदान करने हेतू अनुच्छेद-5 के तहत एफसीए 1980 को उस समय के राज्य पाल ने निलंबित किया था।

14 से 19 सितंबर तक निकलेगी सवर्ण एकता यात्रा, ज्वाला माता की दिव्य ज्योति के होंगे दर्शन

पवन धीमान
हमीरपुर। राजपूत कल्याण सभा की ओर से सवर्ण एकता यात्रा एवं ज्वाला माता की दिव्य ज्योति दर्शन यात्रा का आयोजन 14 से 19 सितंबर तक किया जाएगा। यात्रा के माध्यम से जिला भर में सवर्ण समाज में एकता, सामाजिक सौहार्द और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। यात्रा 14 सितंबर को सुबह 10 बजे नादौन पुल से मां ज्वाला देवी की अखंड ज्योति के साथ शुरू होगी। इसके बाद यह जिला के विभिन्न उपमंडलों और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए 19 सितंबर को जिला मुख्यालय पर संपन्न होगी।

आयकर विभाग ने बट्ट आईटीआई और नर्सिंग कॉलेज में लगाई जागरूकता क्लास, समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बताए फायदे

हामिद खान
चंबा। बट्ट कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग एवं आईटीआई, बोंखरीमोड़ में आयकर विभाग डलहौज़ी द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने के महत्व पर एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रधान आयकर आयुक्त-1 (चंडीगढ़) श्रीमती शालिनी भार्गव कौशल और संयुक्त आयकर आयुक्त (शिमला रेंज) श्री केशव कुमार आनंद के मार्गदर्शन में डलहौज़ी के आयकर अधिकारी श्री विनीत कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ। शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को कर अनुपालन और

समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान विशेषज्ञों ने ई-फाइलिंग पोर्टल, प्री-फिल्ड रिटर्न्स, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26ए एस जैसी आधुनिक डिजिटल सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। नियमित इनकम टैक्स रिटर्न भरने के मुख्य लाभ की जानकारी देतेहए बताय गया कि यह बैंक लोन, वीजा प्रक्रिया और आय के आधिकारिक प्रमाण के रूप में उपयोगी। इसके अलावा टी डी एस रिफंड प्राप्त करने में सुगमता, समय पर रिटर्न भरने से नोटिस, अनावश्यक ब्याज और दंड जैसी कठिनाइयों से बचाव।

11 महीने बाद पानी बिल पहुंचा घर, राहत की किस्तों ने संभाली जेब

हामिद खान
चंबा। पानी की दर तय होने में अटके पेंच के कारण चंबा शहर के उपभोक्ताओं को बिल पाने के लिए 11 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा है। अब जल शक्ति विभाग ने अगस्त 2025 से जून 2026 तक की अवधि का कुल बिल एक साथ जारी कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं पर एकमुश्त भुगतान का दबाव बढ़ गया है। हालांकि, विभाग ने राहत देते हुए उपभोक्ताओं को बिल किस्तों में चुकाने की सुविधा भी प्रदान की है।

अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक (आठ महीने) की बकाया राशि 3552 रुपये बनी है, जिसमें पानी की दर 444 रुपये प्रतिमाह रही है। अप्रैल से जून 2026 तक (तीन महीने) का बिल 1260 रुपये है, जिसके लिए 420 रुपये प्रतिमाह की दर निर्धारित की गई है। इस तरह 11 महीनों की कुल बिल राशि 4812 रुपये है। अप्रैल से जून तक की राशि उपभोक्ताओं को एक साथ जमा करवानी होगी, जबकि अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक की आठ महीने की बकाया राशि को किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है। एक साथ कई महीनों का बिल मिलने से कई उपभोक्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि इतने लंबे समय का बिल एक साथ क्यों जारी किया गया।

क्योंथल क्षेत्र में परंपरानुसार मनाया डगैली पर्व

चमन शर्मा
शिमला। डायनों का पर्व डगैली क्योंथल क्षेत्र में बीती रात परंपरा के अनुसार मनाया गया । बता दें कि प्रदेश में मनाए जाने वाले तीज त्यौहारों की श्रृखंला में सबसे विचित्र पर्व है डगैली । जोकि हर वर्ष रक्षा बंधन पर्व के एक पखवाड़ा उपरांत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुदर्शी व अमावस्या को मनाया जाता है । इस पर्व को विशेषकर जिला शिमला, सिरमौर और सोलन में प्राचीन परंपरा के अनुरूप मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे कृष्ण जन्माष्टमी को भी मनाया जाता है ।

वरिष्ठ नागरिक दौलत राम मेहता, जबर सिंह ठाकुर के अनुसार डगैली को डायनों का पर्व माना जाता है। बताते हैं कि इस पर्व में रात्रि को आसुरी शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत होती है और डायनों द्वारा अपनी कला से अदृष्य नृत्य किया जाता है । बता दें कि अतीत से ही डगैली को सबसे भयावह वाला त्यौहार माना जाता रहा है । इन्होने बताया कि त्यौहार के कुछ दिन पहले स्थानीय देवी देवता के पुजारी घर घर जाकर सुरक्षाचक्र के रूप में देवता के चावल व सरसों के दाने देते हैं जिसे चतुदर्शी की रात्रि को घर के मुख्य दरवाजे पर रखा जाता है ताकि आसुरी शक्तियों का घर में प्रवेश न हो । इसके अतिरिक्त भेखल झाड़ी की टहनियों को भी मंदिर, घर व गौशाला के दरवाजे, खिड़की पर सुरक्षा के रूप में लटकाई जाती है ।

उन्होने बताया कि इस पर्व पर विशेषकर अरबी के पत्तों के पतीड़ जिसे स्थानीय भाषा में धींघड़े कहते हैं, को बनाए जाते है जिसे चौदश तिथि अर्थात डगैली की पहली रात्रि को घर की दलहीज पर तेजधार चाकू अथवा कुल्हाड़ी से काटकर इसके चार टुकड़े बनाए जाते हैं जिसे छत पर जाकर चारों दिशाओं में डायनों के नाम से चढ़ाया जाता हैं ताकि आसुरी शक्तियां कोई नुकसान न कर सके । तांत्रिक डगयाली की रात्रि को साधना के सबसे उपयुक्त समय बताते हैं । इस अमावस्या को शास्त्रों में कुशोत्पाटिनी अमावस्या कहते हैं।

हिम क्वेस्ट टैलेंट सर्च एग्जाम-2026 के विन्नर को मिलेगा इसरो भ्रमण का मौका

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर, हिमाचल के मेधावी विद्यार्थियों के लिए मिनर्वा स्टडी सर्कल ने बड़ा अवसर दिया है। हिम क्वेस्ट टैलेंट सर्च एग्जाम.2026 में आठवीं से 12वीं कक्षा तक प्रत्येक वर्ग में स्टेट टॉप करने वाले विद्यार्थियों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया जाएगा। यानी किताबों में पढ़े अंतरिक्ष विज्ञान और भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों को विद्यार्थी इस बार करीब से देखने और समझने का मौका पाएंगे। हिम क्वेस्ट.2026 की परीक्षा 27 सितंबर को प्रदेशभर में ऑफलाइन आयोजित होगी। इसमें आठवीं, नौवीं, दसवीं तथा 11वीं.12वीं विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को 17 सितंबर तक आवेदन करना होगा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को इसरो भ्रमण के साथ ट्यूशन फीस पर 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाएगी। द्वितीय स्थान पर लैपटॉप और 75 प्रतिशत, जबकि तृतीय स्थान पर टैबलेट और 50 प्रतिशत छात्रवृत्ति मिलेगी। चैथे और पांचवें स्थान के विद्यार्थियों को स्मार्ट घड़ी के साथ 40 प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाएगी। छठे से दसवें स्थान तक रहने वाले विद्यार्थियों को 30 प्रतिशतए 11वें से 20वें तक 25 प्रतिशत तथा 21वें से 50वें स्थान तक 15 प्रतिशत छात्रवृत्ति के साथ आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। 51वें से 150वें स्थान तक आने वाले विद्यार्थियों को भी ट्यूशन फीस में 10 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। राज्य स्तरीय पुरस्कारों के अलावा प्रत्येक जिले के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को जिला टॉपर के रूप में सम्मानित किया

उच्च पाठशाला बलघाड़ में बच्चों ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर, राजकीय उच्च पाठशाला बलघाड़ में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां मुख्य अध्यापक संजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित करवाई गई। इसमें हिमाचल अग्निशमन विभाग के उप अग्निशमन केंद्र झंडुता से उप अग्निशमन अधिकारी भाग सिंह, फायरमैन राकेश कुमार तथा गृह रक्षा कंपनी झंडूता द्वारा बच्चों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं की जानकारी दी तथा बच्चों अध्यापकों एवं मध्याह्न भोजन कर्मचारियों को विभिन्न आपदाओं से बचाव, विशेषकर आग लगने एवं भूकंप के समय बचाव के गुर सिखाए। इसके पश्चात आपदा प्रबंधन प्रभारी सुरेश शर्मा द्वारा पाठशाला में भूकंप से बचाव के लिए एक मॉक ड्रिल करवाई गई। जिसमें छात्रों तथा अध्यापकों की आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बनी विशेष टीमों ने भाग लिया।

डा. अंबेडकर ने दिया शोषित वंचितों को सिर उठाकर जीने का अधिकार: रमेश कौंडल

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर, बिलासपुर जिला की सदर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरमाणा के गांव खतेड़ में नव नियुक्त जोन अध्यक्ष सुन्दर लाल के आवास में बैठक की गई। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष रमेश चन्द कौंडल द्वारा जोन अध्यक्ष सुन्दर लाल को सम्मानित किया। बैठक की शुरुआत करने से पहले भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी को याद किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष रमेश चन्द कौंडल ने कहा कि भारत देश को आजाद करवाने में कांग्रेस पार्टी और देस के क्रांतिकारी युवाओं का महान योगदान रहा है। देश आजाद तो हो गया परंतु हमारा ये समाज अनुसूचित जाति वर्ग फिर भी गुलाम ही रहा। आजाद भारत से पहले अनुसूचित जाति वर्ग गुलाम ही होता था उनको लोगों के घरों में काम करके ही रोजी रोटी मिलती थी, पहले जात पात की इस खाई की वजह से आज भी कही न कही अनुसूचित जाति वर्ग को लोग घृणा से देखते हैं। उन्होंने कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद उन्होंने विधान सभा में जाति का हर दस्तावेज के कालम ही हटा दिया अन्यथा उससे दस्तावेज से कहीं न कहीं भेदभाव किया जाता था।

कांग्रेस पार्टी की सोच और बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान में ही आजादी प्राप्त हुई है। लेकिन यह भी हैरानी का विषय है कि भाजपा के नेताओं की सोच आज भी संविधान के खिलाफ है।

23 किलोमीटर सेलिंग के बाद टीबी मुक्त भारत की जागरूकता रैली

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। गोविंद सागर झील में आयोजित 'संकल्प एक्सपीडिशन-2026' के तीसरे दिन एनसीसी कैडेट्स ने 23 किलोमीटर की सेलिंग पूरी कर नौकायन कौशल, साहस, अनुशासन और टीम भावना का परिचय दिया। कैडेट्स ने चांदपुर से ऋषिकेश होते हुए भराड़ी पुल तक नौकायन किया। प्रशिक्षकों की देखरेख में उन्होंने जल परिस्थितियों के अनुरूप नाव संचालन और आपसी समन्वय के गुर सीखे। सेलिंग के बाद कैडेट्स राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऋषिकेश पहुंचे, जहां 'टीबी मुक्त भारत' के संदेश के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। स्थानीय विद्यालय के कैडेट्स और विद्यार्थियों ने भी इसमें भाग लिया। रैली के माध्यम से टीबी के लक्षण, समय पर जांच, उपचार और बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. केएस चंदेल और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर दीपिका ने कैडेट्स से संवाद कर टीबी की रोकथाम और उपचार संबंधी जानकारी दी। कमांडिंग ऑफिसर कमांडर सज्जन सिंह ने कहा कि अभियान का उद्देश्य कैडेट्स को साहसिक गतिविधियों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी तैयार करना है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य शशि पाल चौहान, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर अब्दुल मजीद, सब लेफ्टिनेंट सुरेश कुमार और चीफ इंस्ट्रक्टर धीरज राठौर मौजूद रहे।

ऑनलाइन कारोबार में मुनाफे का झाँसा देकर धोखा धड़ी का मिल जाए मामला दर्ज

संगराय

जोगिंद्रनगर पुलिस थाना के तहत ऑनलाइन कारोबार में मुनाफा कमाने का झांसा देकर 9.63 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह निवासी गांव रैंस, डाकघर बसोना, तहसील लडभड़ोल, जिला मंडी ने आरोप लगाया कि फेसबुक के माध्यम से सितारा रानी और मीरा रानी नामक महिलाओं ने उसे ई सेलर शॉप ऑनलाइन स्टोर के जरिए कारोबार में लाभ कमाने का झांसा दिया।

पीएनबी आरसेटी ने महिलाओं को दिया उद्यमिता का प्रशिक्षण

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू कुल्लू द्वारा 35 दिवसीय ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 29 महिला प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम समन्वयक लक्ष्मी ने बताया कि 35 दिनों तक चले प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को ब्यूटी पार्लर व्यवसाय के माध्यम से सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रतिभागियों को उद्यमिता की विभिन्न बारीकियों से अवगत करवाते हुए स्वप्रेरणा, व्यवसाय के अवसरों की पहचान एवं उनका उचित उपयोग, निरंतरता, आवश्यक सूचनाओं की खोज, गुणवत्ता प्रबंधन, समस्या समाधान, आत्मविश्वास तथा ग्राहकों को अपने उत्पाद एवं सेवाओं के प्रति आश्वस्त करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में पीएनबी आरसेटी कुल्लू के निदेशक चंद्र नारायण सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रशिक्षुओं को सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक सुझाव देते हुए बाजार प्रबंधन और गुणवत्ता प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार अपनाकर अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इससे वे आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

संक्षिप्त खबरें

गोविंद सागर झील में चल रहे संकल्प एक्सपीडिशन के तहत किया 23 किलोमीटर का सफर

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर, गोविंद सागर झील में आयोजित संकल्प एक्सपीडिशन.2026 के तीसरे दिन एनसीसी कैडेट्स ने दिन की शुरुआत योग एवं हल्के व्यायाम के साथ की। इसके बाद कैडेट्स ने चांदपुर से ऋषिकेश तक नौकायन करते हुए भराड़ी पुल तक का सफर तय किया। दूसरे दिन अभियान के दौरान कैडेट्स ने कुल 23 किलोमीटर की सेलिंग पूरी की। प्रशिक्षकों की देखरेख में कैडेट्स ने नौकायन की तकनीक, जल परिस्थितियों के अनुरूप नाव संचालन, टीमवर्क और आपसी समन्वय के महत्वपूर्ण गुर सीखे। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक.दूसरे के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ते हुए कैडेट्स ने अपने साहस एवं आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। टीबी मुक्त भारत के संदेश के साथ निकली जागरूकता रैली सेलिंग के उपरांत कैडेट्स राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, ऋषिकेश पहुंचे। यहां टीबी मुक्त भारत अभियान के प्रति लोगों एवं बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय विद्यालय के कैडेट्स ने भी इस रैली में भाग लिया। विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य शशि पाल चैहान एवं समस्त स्टाफ ने कमांडिंग ऑफिसर कमांडर सज्जन कुमार, लेफ्टिनेंट कमांडर जतिंदर सिंह, कमांडिंग ऑफिसर, 3 पंजाब नेवल यूनिट भटिंडा, एनसीसी कैडेट्स एवं प्रशिक्षक दल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रैली के माध्यम से कैडेट्स ने टीबी की रोकथामए इसके लक्षणों की पहचानए समय पर जांच एवं उपचार तथा बीमारी के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

जिला परिषद चुनाव के नतीजों को जनादेश बताना भाजपा की गलतफहमी : अनुराग पंडित

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। कांग्रेस के जिला संगठनात्मक महासचिव अधिवक्ता अनुराग पंडित ने कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत को प्रदेश की जनता का जनादेश बताना वास्तविकता से परे है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन पदों के लिए आम मतदाता सीधे मतदान नहीं करता, ऐसे में इन परिणामों को प्रदेश के व्यापक राजनीतिक रुझान से जोड़ना उचित नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में भाजपा ने जोड़-तोड़ और राजनीतिक प्रबंधन के जरिए अपने समर्थित प्रत्याशियों को जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर बैठाया है। पंडित ने कहा कि इस तरह के सीमित चुनाव परिणामों को विधानसभा चुनाव या प्रदेश की जनता की पसंद का आधार नहीं माना जा सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि सुक्खू सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए लगातार फैसले ले रही है। सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ आम लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के लिए विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाएं प्रमुख मुद्दे हैं। अनुराग पंडित ने भाजपा पर आंतरिक गुटबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में लौटने का सपना देखने से पहले पार्टी को अपने भीतर चल रही खींचतान दूर करनी चाहिए।

न्यू कॉम्प्लेक्स प्रणाली प्राथमिक शिक्षा के लिए नुकसानदायक: राकेश पटियाल

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला बिलासपुर की सभी छह खंडों की कार्यकारिणीयों की वर्चुअल बैठक जिला प्रधान राकेश पटियाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें जिला के प्राथमिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं तथा आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला प्रधान राकेश पटियाल ने बताया कि न्यू कॉम्प्लेक्स प्रणाली के प्राथमिक शिक्षा को होने वाले नुकसान अब धीरे-धीरे सामने आने शुरू हो गए हैं। देखने में आ रहा है कि बिलासपुर जिले में 65 प्रतिशत प्राथमिक पाठशालाएं एकल तथा बिना अध्यापक के हो गई हैं। ऐसा बताया गया था कि कॉप्लेक्स मुखिया अर्थात प्रिंसिपल अपने स्तर पर इन पाठशालाओं को अपनी पाठशालाओं से शिक्षक प्रतिनियुक्त करेंगे, जिससे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों कमी दूर हो जाएगी। किंतु बड़े खेद का विषय है कि ऐसी स्थिति बन गई है कि प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए फिर से पहले की व्यवस्था के अनुसार ही बीईईओ कार्यालय या उपनिदेशक कार्यालय से ही जहां कहीं किसी प्राथमिक पाठशाला में दो शिक्षक हैं वहीं से किसी एक प्राथमिक शिक्षक को बिना शिक्षक की पाठशाला में प्रतिनियुक्ति आदेश करने पड़ रहे हैं ताकि शिक्षक की कमी से जूझ रही प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने वाले नौनिहालों की शिक्षा प्रभावित न हो जबकि संबंधित कॉम्प्लेक्स से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस प्रणाली को लागू करने के दुष्परिणाम शिक्षा जगत पर कितने भयानक होंगे। इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। संघ का मानना है कि राज्य के प्राथमिक पाठशालाओं में रिक्त पड़े लगभग 5000 प्राथमिक शिक्षकों के पदों को सरकार शीघ्र भरने की प्रक्रिया शुरू करे ताकि बेरोजगार जेबीटी प्रशिक्षित युवाओं का भी भला हो तथा प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भी भला हो किंतु इसके विपरीत विभाग तथा सरकार ने जेबीटी भर्ती के प्रति उदासीन रवैया अपनाया हुआ है। बैठक में सभी खंड प्रधानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राज्य कार्यकारिणी प्राथमिक शिक्षा को बचाने के लिए जो भी संघर्ष का निर्णय लेगी। उसमें वे सदैव तन, मन, धन से सहयोग के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री कर्मचारी हितैषी हैं तथा वे शिक्षा तथा शिक्षकों की समस्याओं के प्रति गंभीर हैं किंतु उनकी मानी गई किसी भी बात का विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। राकेश पटियाल ने बताया कि सभी खंड प्रधान इस संघर्ष में पूरी तरह से तैयार हैं तथा राज्य कार्यकारिणी राज्य प्रधान रमेश शर्मा के नेतृत्व में जो भी आगामी निर्णय लेती है

संगठन को मज़बूत करने के लिए बूथ स्तर पर एक जुट हो कर कार्य करें कार्यकर्ता : जीवन ठाकुर

टीम एक्शन इंडिया
संगराय

जोगिंद्रनगर जोगिंद्रनगर ब्लॉक कांग्रेस की नई कार्यकारणी की पहली बैठक वीरवार को लोक निर्माण विभाग जोगिंद्रनगर के विश्राम गृह में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट इंद्र सिंह धीमान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर ने विशेष रूप से शिरकत की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकारणी सदस्यों का भव्य स्वागत किया।इस दौरान कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर एकजुट होकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर निर्भर है और प्रत्येक कार्यकर्ता को पार्टी की नीतियों एवं सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने का आह्वान किया। चौंतड़ा जोन के अध्यक्ष भगवान दास, मकरीड़ी जोन के अध्यक्ष दुर्गा दास ठाकुर, भराडू जोन के अध्यक्ष पदम देव तथा लडभड़ोल जोन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कैप्टन वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आएगी।

चारों जोन के अध्यक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूत करने तथा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का संकल्प लिया।

सितंबर में विभिन्न स्टेशनों पर वाहनों की पासिंग व ड्राइविंग टेस्ट का शेड्यूल जारी

कुल्लू। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आकांक्षा शर्मा ने बताया कि सितंबर 2026 के लिए जिले के विभिन्न स्टेशनों पर वाहनों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरटीओ कुल्लू में वाहनों की पासिंग 10, 17 और 28 सितंबर को तथा ड्राइविंग टेस्ट 16 सितंबर को आयोजित होंगे। आरएलए कुल्लू में ड्राइविंग टेस्ट 21 सितंबर को होंगे। इसी प्रकार आरएलए मनाली में वाहनों की पासिंग 7 और 19 सितंबर तथा ड्राइविंग टेस्ट 8 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे।

युवाओं को रोजगार देने के साथ स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करें उद्योग : त्रिलोक जमवाल

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर/चांदपुर स्थित सूर्य किया शोरूम में किया मोटर्स की नई किया सोरेंटो का अनावरण सदर विधायक त्रिलोक जमवाल ने किया। इस अवसर पर विधायक ने नई गाड़ी के शुभारंभ पर सूर्य किया शोरूम की पूरी टीम और किया मोटर्स को शुभकामनाएं दीं। विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों को युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज का युवा केवल नौकरी की तलाश में नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी प्रतिभा और हुनर के दम पर अपना व्यवसाय शुरू करने और दूसरों को रोजगार देने की क्षमता भी रखता है। ऐसे में नए उद्योगों, स्टार्टअप और स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवा नए स्टार्टअप शुरू कर आत्मनिर्भर बनें और रोजगार मांगने वाले के बजाय रोजगार देने वाले बनें। इसके लिए आधुनिक तकनीक, नए व्यवसायिक अवसर और उद्योग जगत का सहयोग युवाओं को मिलना जरूरी है। नई किया सोरेंटो के अनावरण पर विधायक ने कहा कि नई तकनीक, आकर्षक डिजाइन, बेहतर सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं से लैस यह वाहन वाहन प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

खो-खो प्रतियोगिता में कोटमोरस ने कैहनवाल की टीम को पराजित किया

टीम एक्शन इंडिया

मंडी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कैहनवाल में आज अंडर-14 छात्र वर्ग की सदर-1खण्डस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता 10 से 12 सितंबर तक 3 दिन तक चलेगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्याम लाल ठाकुर, अध्यक्ष, कबड्डी एसोसिएशन जिला मंडी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ-साथ उनमें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास करते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों से खेल भावना एवं अनुशासन के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य उमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस खण्डस्तरीय प्रतियोगिता में 18 विद्यालयों के लगभग 189 छात्र विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए बेहतर मंच प्रदान करना तथा उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना है। प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों, शारीरिक शिक्षकों तथा टीम प्रभारियों को प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। आज खेले गए मैचो में बैडमिंटन प्रतियोगिता में एस.वी.एम. मंडी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मझवाड़, राजकीय उच्च विद्यालय मेहंणी ने पीएम श्री मंडी तथा सीबीएसई मंडी ने बडोग को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।

संघर्ष समिति जल्दी ही दिल्ली आयुष मंत्रालय कूच करेगी : गुरु शरण परमार

टीम एक्शन इंडिया
संगराय

जोगिंद्रनगर क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र बचाओ संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय आयुष मंत्रालय से मुलाकात करने के लिए जल्दी ही जाएगा और अपनी एक सूत्रीय माँग को पुरजोर तरीके से रखेगा कि यह संस्थान किसी भी कीमत पर जोगिंदर नगर से बाहर नहीं जाएगा द्य यह जानकारी देते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष गुरु शरण परमार ने बताया कि अगले एक सप्ताह के अंदर ही संघर्ष समिति को आयुष मंत्रालय में अपनी बात रखने का समय राज्य सभा सांसद अनुराग शर्मा व कांगड़ा लोकसभा से सांसद राजीव भारद्वाज की मध्यस्तता से समय मिलने वाला है द्य 11सितम्बर को दोपहर 01:00 बजे संघर्ष समिति ने एक आम सभा बुलाई है इसमें जिस भी संघर्ष के साथी ने किसी भी रूप में संघर्ष समिति के आज तक के सफर में साथ दिया है उन सब के सुझाव भविष्य की रणनीति बारे लिए जाएंगे द्य संघर्ष समिति ने अब आने वाले समय में जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र को 4-5 जोन में बांटकर लड़ भड़ोल, चौंतड़ा, मच्छयाल, गलू आदि क्षेत्रों में जाकर स्थानीय स्तर पर जनसभाएं करने का प्रस्ताव रखा है जो कि उन क्षेत्रों के संघर्ष समिति के साथ जुड़े जागरूक जोगिंदर नगर वासियों के साथ मिल बैठकर तय की जाएगी द्य क्रमिक अनशन के 22वें दिन राम चंदर पॉल प्रधान ग्राम पंचायत मझारनू, राकेश कुमार, कालिदास ठाकुर पूर्व उप प्रधान ग्राम पंचायत बाता री

छकोह में कबड्डी-बैडमिंटन में हरनोड़ा स्कूल का दबदबा, विजेता बनने के साथ ऑल राउंड बेस्ट स्कूल का खिताब

टीम एक्शन इंडिया
कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरनोड़ा के खिलाड़ियों ने अंडर-19 खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों ने कबड्डी और बैडमिंटन में विजेता का खिताब हासिल करने के साथ-साथ ओवरऑल ऑल राउंड बेस्ट स्कूल का खिताब भी अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता 7 से 9 सितंबर 2026 तक छकोह में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में हरनोड़ा के खिलाड़ियों ने प्रतिभा, मेहनत, अनुशासन और खेल भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि में विद्यालय की बेटियों की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। नेहा कुमारी, अनमोल, कृतिका, हर्षिता, रिया, सारिका, सानिया, साक्षी, दीपिका, नेहा, खुशी और संध्या ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर विद्यालय को गौरवान्वित किया। इन खिलाड़ियों ने साबित किया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। मैदान पर उनके आत्मविश्वास, अनुशासन, संघर्ष और जीत के लिए जुनून ने सभी को प्रभावित किया। उनकी सफलता अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणा बनी है। विद्यालय के डीपीई क्रांति मोहन के कुशल मार्गदर्शन और खिलाड़ियों की निरंतर मेहनत का इस सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। शानदार उपलब्धि के बाद विद्यालय परिवार की ओर से खिलाड़ियों का स्वागत किया गया तथा उनके उत्साहवर्धन के लिए लंच पार्टी का आयोजन भी किया गया। प्रधानाचार्य जगदीश सिंह ने सभी खिलाड़ियों को शानदार सफलता के लिए बधाई दी।

नाहन में अतिक्रमण पर चला प्रशासन और नगर परिषद का संयुक्त चाबुक

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन अतिक्रमण के शिकंजे में जकड़े नाहन शहर को अब अवैध कब्जों से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शहर की सड़कों, गलियों और सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर बैठे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ वीरवार को प्रशासन और नगर परिषद ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई की शुरुआत दिल्ली गेट से मोहल्ला गोबिंदगढ़ तक की गई, जहां सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। कार्रवाई शुरू होते ही पूरे शहर में अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया। संयुक्त कार्रवाई में एसडीएम नाहन राजीव संख्यान, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार, पुलिस, राजस्व विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। टीम ने सड़क किनारे सरकारी भूमि पर किए गए कब्जों को हटाने के साथ-साथ लंबे समय से पड़े कबाड़ और कंडम वाहनों पर भी कार्रवाई की। नगर परिषद परिसर के नीचे गोबिंदगढ़ क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े पुराने स्कूटर, कंडम फ्रिज और अन्य सामान को जेसीबी की सहायता से हटाकर कब्जे में लिया गया।कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने हल्का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि और सार्वजनिक रास्तों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को शहर की यातायात व्यवस्था, सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधा की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।छह माह पहले दिए थे नोटिस, अब कार्रवाई की बारीनगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अवैध कब्जाधारियों को करीब छह माह पहले नोटिस जारी किए गए थे। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल गोबिंदगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि चरणबद्ध तरीके से नाहन शहर के उन सभी हिस्सों में कार्रवाई की जाएगी, जहां सरकारी जमीन, सड़क या सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण किया गया है।

H.P.P. W.D
HP14C 1672

पैड़ी स्कूल में तीन दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

टीम एक्शन इंडिया
कमल शर्मा

नेरचौक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैड़ी में तीन दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में सरकारी और निजी क्षेत्र के 25 स्कूलों के 328 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। तीन दिनों तक खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, योग और शतरंज सहित विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को खेलों में हमेशा खेल भावना के साथ भाग लेना चाहिए।

आधुनिक दौर में भी जीवित है सदियों पुरानी डगैली पर्व की परंपरा, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मनाया जाता है यह पर्व

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहां आज भी अनेक ऐसी प्राचीन परंपराएं, रीति-रिवाज और त्योहार जीवित हैं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आस्था के साथ निभाया जाता है। इन्हीं परंपराओं में शामिल है डगैली पर्व और अदृश्य डगैली नृत्य।सिरमौर, शिमला, सोलन, मंडी और कुल्लू के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व को मनाए जाने की मान्यता है। हालांकि डगैली पर्व की शुरुआत कब और क्यों हुई, इसके पीछे कोई स्पष्ट ऐतिहासिक या प्रमाणिक तथ्य सामने नहीं आते। अलग-अलग क्षेत्रों में इसे अलग-अलग समय पर मनाया जाता है।और इसका नाम भी अलग अलग है जैसे कहीं इसे डायन पर्व,तो कहीं डंगास भी कहा जाता है और इसको अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है । स्थानीय मान्यता के अनुसार, डगैली का अर्थ डायनों का पर्व माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह पर्व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की रात मनाया जाता है, जबकि कुछ स्थानों पर इसके पांच से आठ दिन बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी को यह परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि इन रातों में डायन, भूत और पिशाच जैसी अदृश्य शक्तियां विचरण करती हैं और नृत्य करती हैं। स्थानीय विश्वास के अनुसार, इस कथित अदृश्य नृत्य को सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता। इसे केवल तांत्रिक अथवा देव परंपरा से जुड़े गुर यानी घणिता ही देख सकते हैं। इसी मान्यता के चलते डगैली पर्व से पहले ग्रामीण परिवार अपने घरों, पशुशालाओं और खेतों की सुरक्षा के लिए पारंपरिक उपाय करते हैं। रक्षाबंधन के दिन पुरोहितों द्वारा यजमानों को बांधा गया रक्षा सूत्र डगैली पर्व के बाद ही खोला जाता है। वहीं पुरोहितों और कुलदेवता के गुर द्वारा दिए गए अभिमंत्रित चावल और सरसों के दाने डगैली से पहले घर, पशुशाला और खेतों में छिड़के जाते हैं। मान्यता है कि इससे परिवार, पशुधन और फसलों को किसी अनिष्ट से सुरक्षा मिलती है।

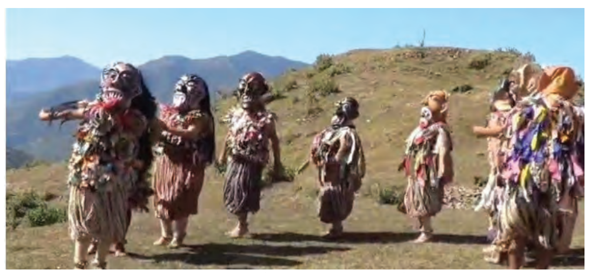

3% डीए समेत लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान की मांग, एचआरटीसी पेंशनरों ने बैठक में जताई नाराजगी

टीम एक्शन इंडिया
विमम ग्रोवर

परवाणू। हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर परवाणू इकाई की मासिक बैठक वीरवार को एचआरटीसी कर्मशाला स्थित काली माता मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता इकाई के उपप्रधान राम सरन ठाकुर ने की। बैठक में पेंशनरों ने निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने पर नाराजगी जताई। इकाई प्रधान देव राज शर्मा ने कहा कि लंबे समय से मांग उठाए जाने के बावजूद पेंशनरों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री द्वारा इस संबंध में किए गए आश्वासन के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। देव राज शर्मा ने कहा कि जनवरी 2016 के बाद से सेवानिवृत्त पेंशनरों के विभिन्न आर्थिक लाभ भी लंबित हैं। न्यायालय के फैसले के बाद भी डीए का पूर्ण भुगतान नहीं होने पर उन्होंने चिंता जताई। उनके अनुसार कुछ मामलों में

श्री रेणुकाजी-नाहन मार्ग पर पलटा ट्राला, यातायात बाधित

एसपी जैरथ

नाहन, श्री रेणुकाजी-नाहन मार्ग पर नैहली से आगे क्यारटू के पास गुरुवार सुबह लोहे के एंगल लेकर जा रहा एक ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।जानकारी के अनुसार ट्राला नाहन की ओर से आ रहा था। क्यारटू के पास एक मोड़ पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ट्राला सड़क पर ही पलट गया। गनीमत रही कि हादसे के समय पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की द्वितीय तिमाही बैठक आयोजित

टीम एक्शन इंडिया
मनीष

सोलन। सहायक आयुक्त डॉ. पूनम बंसल ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में युवाओं के समग्र विकास एवं उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में माय भारत पोर्टल पर अधिक से अधिक युवाओं का पंजीकरण करवाना नितांत आवश्यक है। डॉ. पूनम बंसल आज यहां नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से आयोजित युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की द्वितीय तिमाही बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। सहायक आयुक्त ने कहा कि आज के युग में युवाओं को तनाव प्रबंधन पर जागरूक एवं शिक्षित करना समय की आवश्यकता है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ ही गैर सरकारी संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से माय भारत के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

उन्होंने माय भारत से पंजीकृत युवाओं को विभिन्न पंचायतों में ग्रामीण स्तर पर भेज कर नशाबंदी तथा स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित आमजन को जागरूक करवाने के निर्देश दिए। बैठक का प्रमुख केंद्र विकसित भारत यंग लीडर्स 2027 के अंतर्गत आयोजित 'विकसित भारत क्विज' रहा।

संक्षिप्त खबरें

शिलाई व रेणूका में 2 सड़क हादसों में 5 घायल, चालकों के खिलाफ मामला दर्ज

अमरपुर मुहल्ले के शिव मंदिर के पालने से कान्हाजी की मूर्ति गायब, जांच की उठी मांग

नाहन 10 सितंबर (एसपी जैरथ):-नाहन के अमरपुर मोहल्ले के शिव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर पालने में रखी गई कान्हाजी की मूर्ति छठी कार्यक्रम की तैयारी के दौरान गायब मिली। पंडित ने पालना खाली देखकर स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी। घटना से चिंतित वार्ड नंबर पांच के लोगों ने बुधवार को उपायुक्त सिरमौर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल पार्षद सीमा अत्री ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी के लिए अमरपुर मोहल्ले के शिव मंदिर में पालना सजाकर उसमें कान्हाजी की मूर्ति रखी गई थी। इसके बाद मंदिर में छठी कार्यक्रम की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान पंडित ने पालना देखा तो उसमें मूर्ति मौजूद नहीं थी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन मूर्ति का पता नहीं चल

रेड क्रॉस सोसायटी मानवता की सेवा में निरंतर तत्पर - मनमोहन शर्मा

HELPING ROOM
INFIRMARY

टीम एक्शन इंडिया
मनीष

सोलन। उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि रेड क्रॉस सोसायटी का उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करना है। मनमोहन शर्मा आज यहां ज़िला सोलन रेड क्रॉस सोसाइटी सोलन के सौजन्य से राजकीय महाविद्यालय कण्डाघाट में यूथ रेड क्रॉस यूनिट सहायता कक्ष का लोकार्पण करने के उपरांत उपस्थित छात्रों व अन्य को सम्बोधित कर रहे थे। मनमोहन शर्मा ने कहा कि इस यूनिट के खुलने से जहां ज़रूरतमंद लोगों को सहायता मिलेगी वहीं युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ आपदा एवं अन्य संवेदनशील परिस्थितियों में मानवीय मूल्यों, मानवता की सेवा के प्रति संवेदनशीलता एवं नेतृत्व की भावना विकसित करने का अवसर भी प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि ज़िला की इस प्रथम यूनिट के बनने से रेड क्रॉस की सेवाओं में व्यापक विस्तार होगा। रेड क्रॉस प्रदेश, ज़िला व उपमण्डल स्तर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। उपायुक्त ने आमजन से आग्रह किया कि वह इस सुविधा की जानकारी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाए ताकि वह इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसायटी मानवता की सेवा में निरंतर तत्पर रहती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं देती है। उन्होंने युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में रेड क्रॉस सोसायटी से जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी से समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसायटी के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया।

जिला रेड क्रॉस सोसायटी सोलन के उप संरक्षक लेखराज कौशिक ने कहा कि ज़िला के अंतर्गत विद्यालयों, महाविद्यालयों सहित 143 जूनियर रेड क्रॉस यूनिट व यूथ रेड क्रॉस यूनिट बनाए गए हैं, इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा गया है। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी कण्डाघाट गोपाल चंद शर्मा, राजकीय महाविद्यालय कण्डाघाट के प्रधानाचार्य डॉ. मदन लाल मनकोटिया, स्वास्थ्य विभाग के डॉ. पीयूष शर्मा, रेड क्रॉस यूनिट कण्डाघाट के प्रभारी राज लक्ष्मी नेगी सहित रेड क्रॉस के सदस्य, कर्मचारी व छात्र उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
"NOTICE INVITING TENDERS"

The Executive Engineer, Una Division HPPWD Una H.P. on behalf of Governor of H.P. invites the online bids on percentage rate, in electronic tendering system, in 2 cover system for the under mentioned works from the eligible and approved contractors/ Firms registered with HPPWD Department.

Sr. No.	Name of work	Estimated cost	Staring date of Downloading bid	Earnest Money	Cost of tender (in Rs)	Deadline for submission of bid	Time Limit	Eligible class of contractor.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Construction of Health Wellness Centre building with residence at Rampur in District Una (HP) (SH:C/O Building portion, Water supply and Sanitary installation, Rain water harvesting tank , Septic Tank and retaining wall etc.) (Deposit work)	75,57,627/-	18.09.2026 up to 10.00 A.M.	1,51,200/-	2000/-	24.09.2026 up to 10.00 A.M.	Nine Months	Class-B & C

NOTE-The bidders are advised to note other details of tenders from the departmental website: www.hptenders.gov.in. The Date of Technical Bid opening 24.09.2026 at 11.00 A.M.

Executive Engineer
Una Division, HP: PWD, Una.
On behalf of Governor of H.P.

RO No. 3254/2026-2027

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
"NOTICE INVITING TENDERS"

The Executive Engineer, Una Division HPPWD Una H.P. on behalf of Governor of H.P. invites the online bids on percentage rate, in electronic tendering system, in 2 cover system for the under mentioned works from the eligible and approved contractors/ Firms registered with HPPWD Department.

Sr. No.	Name of work	Estimated cost	Staring date of Downloading bid	Earnest Money	Cost of tender (in Rs)	Deadline for submission of bid	Time Limit	Eligible class of contractor.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Repair & maintenance on link road to village Fatehpur km.0/0 to 1/200 (SH:P/L Interlocking cement concrete paver blocks at RD.0/990 to 1/085) (Under BPCL Deposit)	11,01,968/-	17.09.2026 up to 10.00 A.M.	22,100/-	500/-	22.09.2026 up to 10.00 A.M.	Two months	Class-D & C

NOTE-The bidders are advised to note other details of tenders from the departmental website: www.hptenders.gov.in. The Date of Technical Bid opening 22.09.2026 at 11.00 A.M.

Executive Engineer
Una Division, HP: PWD, Una.
On behalf of Governor of H.P.

RO No. 3246/2026-2027

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
e-Procurement Notice

INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HPPWD Bangana Division Distt Una H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids for percentage rate, in electronic tendering in 2 Cover System for the below mentioned works from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD Department.

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost	EMD	Time Limit	Cost of Tender	Eligible class of Contractor
1	R.R.D. on Various roads under HPPWD Sub-Division DBR-Basal (SH: Painting of Bridges, Culverts, Kilometer stone & Sign Board etc.)	Rs. 2,39,867.00	Rs. 4,800.00	Two Month	Rs. 350.00	D
2	R.R.D. on Various roads under HPPWD Sub-Division Bangana (SH: Painting of Bridges & Writing of Sign Boards etc. at Section Bangana-I & Bangana-II)	Rs. 2,38,630.00	Rs. 4,800.00	Two Month	Rs. 350.00	D
3	C/o Memorial Smarak of Braveheart Late Constable/GD Om Prakash in Govt. Primary School at Badsala Tehsil & Distt. Una (HP) (Deposit Work)	Rs. 3,17,250.00	Rs. 6,400.00	Two Months	Rs. 350.00	D

The bidders are advised to note other details / tender document / eligibility conditions from the department website https://hptenders.gov.in. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA)

Key Dates:

1.	Date of Online Publication	14.09.2026	10:00 HRS
2.	Document Download Start and End Date	14.09.2026	10:00 HRS
		20.09.2026	Up to 16:00 HRS
3.	Bid Submission Start and End Date	14.09.2026	10:00 HRS
		20.09.2026	Up to 16:00 HRS
4.	Date of Technical Bid opening	21.09.2026	11:00 HRS
5.	Evaluation of Technical Bid	Evaluation of technical Bid will be followed after verification of the documents.	

1. TENDER DETAILS:
b) The Tender Documents shall be uploaded online in 2 Covers:
c) Cover 1: shall contain scanned copies of all "Technical Documents/ Eligibility Information".
Cover2: shall contain "BOQ/Financial Bid", where contractor will quote his percentage rate offer.

2. SUBMISSION OF ORIGINAL DOCUMENTS: Successful bidder shall have to submit the original documents physically with the concerned authority before issue of Letter of award of the work. It may be noted that in case any uploaded scanned document is found to be false / forged at any stage, the bidder shall be debarred for tendering in HPPWD in future as per his affidavit / undertaking submitted along with his bid as per Hon'ble High Court Judgment in CWP NO. 6371/2021.

3. BID OPENING DETAILS: The bids shall be opened on **21.09.2026** at **11:00** HRS in the office Executive Engineer, Bangana Division HPPWD Bangana H.P. by the authorised officer. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

4. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 45 days after the deadline date for bid submission.

5. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond his control. The Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website / tender portal for the latest information related to the tender.

Executive Engineer
HPPWD Division Bangana
Distt Una H.P on behalf of
Governor of Himachal Pradesh

RO No. 3296/2026-2027

नशे के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी : प्रियंका वर्मा

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

नाहन जिला सिरमौर में नशे के दुरुपयोग की रोकथाम तथा जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आज उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्ययोजना के अंतर्गत एक दिवसीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों, विशेषकर युवाओं को जागरूक करने के साथ-साथ नशे की रोकथाम, पहचान, उपचार एवं पुनर्वास के लिए विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा। इस दौरान उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। उन्होंने कहा कि नशे की आदत न केवल युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है, बल्कि परिवार और पूरे समाज को भी प्रभावित कर रही है। नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ रोकथाम, जागरूकता और पुनर्वास जैसे उपायों को अपनाकर बहुआयामी रणनीति के तहत इस समस्या के समाधान के लिए कार्य किया जाए।

नशा-मुक्त हिमाचल का सपना साकार करने के लिए शैक्षणिक संस्थान, खेल संगठन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं तथा समाज मिलकर सामूहिक प्रयास करें। उन्होंने अभिभावकों व अध्यापकों से बच्चों के व्यवहार में आ रहे बदलाव पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा।

उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से नशा-मुक्त हिमाचल बनाने और इसे जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सक्रिय सहयोग देने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत तहसील कल्याण अधिकारी शिलाई विजय सिंह द्वारा प्रतिभागियों के स्वागत एवं कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करने के साथ हुई। इसके उपरांत कलगीधर ट्रस्ट बड़ू साहिब की ओर से सहायक प्रोफेसर मनीषा सहगल ने नशे की रोकथाम, जागरूकता एवं समय रहते हस्तक्षेप के विषय पर प्रस्तुति दी।

पांवटा में नाहन के तस्कर को पकड़ कर 5.76 ग्राम चिट्टा बरामद किया

एसपी जैरथ

नाहन पांवटा साहिब में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाहन शहर व आसपास के क्षेत्र में लंबे अरसे नशीले पदार्थों की तस्करी में लगे एक नाहन के कच्चा टैंक निवासी को धर दबोचा आरोपी तस्कर के कब्जे से 5.76 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जिले के एसपी एनएस नेगी ने बताया कि स्ढ नाहन जिला सिरमौर की पुलिस टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 5.76 ग्राम चिट्टा बरामद क्रिया है। आरोपी के हिरासत में ले लिया गया है। नेगी ने बताया कि पुलिस टीम गश्त के दौरान जब रैनबैक्सी चौक के पास मौजूद थी तो पुलिस टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रोहित विक्रम निवासी कच्चा टैंक नाहन, जिला सिरमौर, काफी समय से चिट्टा/स्मैक बेचने का धन्धा नाहन व आसपास के ईलाका में करता है।

उपायुक्त किरण भड़ाना ने पीएम श्री राजकीय केंद्र प्राथमिक विद्यालय केलांग का किया निरीक्षण

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने आज पीएम श्री राजकीय केंद्र प्राथमिक विद्यालय केलांग का दौरा कर विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं और अधोसंरचना का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी पढ़ाई, स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं तथा सामने आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनकी आवश्यकताओं को जानने में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने विद्यार्थियों से कक्षाओं, पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं के बारे में फीडबैक लिया। बच्चों ने भी अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष साझा किया। उन्होंने विद्यालय के शिक्षकों से भी बातचीत कर शिक्षण व्यवस्था तथा विद्यालय में मौजूद अधोसंरचना संबंधी कमियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ-साथ स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध करवाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, शौचालयों, कक्षाओं, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्यालय में मौजूद कमियों को दूर करने तथा आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।

12 सितंबर को कुल्लू, मनाली व बंजार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

टीम एक्शन इंडिया
श्याम कुल्वी

कुल्लू, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के तत्वावधान में 12 सितंबर, 2026 को जिला न्यायालय कुल्लू सहित मनाली और बंजार न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल, जमीनी विवाद, बैंक से संबंधित विवाद, वैवाहिक विवाद तथा विशेष रूप से कम राशि के चेक से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर मोटर व्हीकल लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोटर व्हीकल चालानों का भी निपटारा किया जाएगा। जिन व्यक्तियों के उपरोक्त श्रेणी के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे अपने मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से किया जाता है। इसमें किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती, बल्कि आपसी समझौते के आधार पर विवाद का समाधान किया जाता है। उन्होंने आमजन से लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू के दूरभाष नंबर 01902-222378 पर संपर्क किया जा सकता है।

सिरमौर की दवा इकाई के खिलाफ डीसीए ने अनुपालन पूरा होने तक उत्पादन पर रोक

टीम एक्शन इंडिया
एसपी जैरथ

Health
Stuff

नाहन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब स्थित फार्मास्युटिकल इकाई मैसर्स वेलक्योर रेमेडीज के खिलाफ ड्रग्स कंट्रोल प्रशासन (DCA) ने कड़ी नियामक कार्रवाई की है। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण एवं अनुपालन सत्यापन के दौरान इकाई में गंभीर कमियां पाए जाने के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार ने बताया कि दवा निर्माण इकाई का राज्य एवं केंद्र के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा अनुपालन सत्यापन किया गया। इस दौरान पहले निरीक्षण में सामने आई कुछ कमियां अभी भी बरकरार पाई गईं। नियामक अधिकारियों ने दवा निर्माण से जुड़े मानकों और आवश्यक अनुपालन को गंभीरता से लेते हुए फर्म के खिलाफ कार्रवाई की है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दवा निर्माण इकाइयों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन इकाइयों में तैयार होने वाली दवाएं सीधे मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। ऐसे में किसी भी गंभीर गैर-अनुपालन की स्थिति में नियामक स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित फर्म ने नियामक अधिकारियों से अतिरिक्त समय मांगा था।

संपादकीय

जल बचाने की मुहिम में जनभागीदारी जरूरी

भारत में पानी की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कई इलाकों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है, तालाब और कुएं सूख रहे हैं तथा खेती और पीने के पानी के लिए भूजल पर निर्भरता बढ़ रही है। ऐसे समय में पानी बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं हो सकती। इसमें आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। इसी सोच के साथ जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया गया है। 6 सितंबर 2024 को शुरू किए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को बचाना, भूजल स्तर बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर पानी के स्त्रोतों को मजबूत करना है। इसके तहत कम खर्च में जल संरक्षण की संरचनाएं बनाने, पुराने और बंद पड़े नलकूपों को फिर से उपयोगी बनाने तथा स्थानीय जरूरत के अनुसार जल संरक्षण के उपाय करने पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान की खास बात यह है कि इसमें सरकार के साथ आम जनता, पंचायतें, सामाजिक संगठन और कंपनियां भी जुड़ सकती हैं। इसका आधार तीन सी हैं- समुदाय, कंपनियों का सामाजिक दायित्व और लागत। यानी समुदाय की भागीदारी, कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी और कम खर्च में जल संरक्षण। इससे जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना न बनाकर जन-अभियान बनाने की कोशिश की जा रही है। इस दिशा में बड़ी संख्या में जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गई हैं। पहले चरण के तहत मई 2025 तक देश में 27 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गईं। इसके बाद जून 2025 में दूसरा चरण शुरू किया गया। मई 2026 तक डेढ़ करोड़ से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई जा चुकी थीं। 3 सितंबर 2026 तक यह संख्या एक करोड़ 58 लाख से अधिक हो गई। यह आंकड़ा बताता है कि देश में जल संरक्षण को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। केवल संरचनाएं बना देना काफी नहीं है। उनका सही स्थान पर बनना, नियमित रखरखाव और सही उपयोग भी जरूरी है। यदि बारिश का पानी इन संरचनाओं तक पहुंचे ही नहीं या कुछ वर्षों बाद वे मिट्टी और कचरे से भर जाएं तो उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए स्थानीय लोगों को इनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। भारत में पानी बचाने की परंपरा पहले से रही है। गांवों में तालाब, कुएं, बावड़ियां, जोहड़ और छोटे बांध लोगों की जरूरत पूरी करते थे। हरियाणा और राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में आज भी पुराने जल स्त्रोत इसकी याद दिलाते हैं। आधुनिक विकास के दौरान हमने इन स्त्रोतों की उपेक्षा की और भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब समय है कि पुरानी समझ को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ा जाए। इसी उद्देश्य से जल संचय जन भागीदारी को वर्षा जल संचयन अभियान से भी जोड़ा गया है। जून 2026 में इसे जल शक्ति अभियान–वर्षा जल संचयन के साथ मिलाकर नया रूप दिया गया। इसका सीधा संदेश है- बारिश की हर बूंद को व्यर्थ बहने से रोकना और उसे जमीन में पहुंचाना।

नई दिल्ली कार्यालय
एक्शन बालाजी हाउस, बी-244, मजलिस पार्क, दिल्ली- 110033

उत्तरी दिल्ली कार्यालय
शक्ति कॉम्पलैक्स, 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली- 110042

चंडीगढ़ कार्यालय
फर्स्ट फ्लोर, देश सेवक बिल्डिंग, सेक्टर- 29डी, चंडीगढ़

पंजाब कार्यालय
7/2, थर्ड फ्लोर, मोनिका, टावर, ईआर-146, पक्का बाग, मिलाप चौक, जालंधर

करनाल कार्यालय
224, सेक्टर 32पी, करनाल- 132001

सोनीपत कार्यालय
ऑफिस no. 11, ग्राउंड फ्लोर पवन मेगा मॉल सुभाष चौक सोनीपत

शिमला कार्यालय
किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला- 171001

ऊना कार्यालय
कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना-174303

देहरादून कार्यालय
7/1, बल्लूपुर रोड़, कृष्णा नगर चौक, देहरादून

साझा नागरिकता राष्ट्र निर्माण में भारतीय मुस्लिम की भूमिका

अल्ताफ मीर

> ये मूल्य रोजमर्रा के व्यवहार के माध्यम से सार्थक हो जाते हैं। दूसरों की गरिमा का सम्मान करना, कानून का पालन करना, पूर्वाग्रह को अस्वीकार करना और लोकतांत्रिक जीवन में रचनात्मक रूप से भाग लेना सभी नागरिकों द्वारा साझा की जाने वाली जिम्मेदारियां हैं। भारतीय मुसलमान, हर दूसरे समुदाय की तरह, नागरिक गतिविधियों में भाग लेकर, संवाद को प्रोत्साहित करके और युवाओं के बीच ज़िम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत कर सकते हैं। डिजिटल युग ने नागरिकता में एक और आयाम जोड़ा है

भारत दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक है, जिसमें विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के लोग हैं। यह विविधता सदियों से विकसित हुई है, जिसमें समुदायों ने देश के सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन में योगदान दिया है। भारतीय मुसलमान इस इतिहास का अभिन्न अंग हैं। उनका योगदान वास्तुकला, साहित्य, व्यापार, शिक्षा, लोक प्रशासन और स्वतंत्रता संग्राम में देखा जा सकता है। जैसे-जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ता है, सवाल केवल यह नहीं है कि भारतीय मुसलमान देश के भविष्य में कैसे फिट होते हैं, बल्कि वे एक मजबूत, समावेशी और समृद्ध भारत में और कैसे योगदान दे सकते हैं। साझा नागरिकता का विचार इस ज़िम्मेदारी को देखने का एक महत्वपूर्ण तरीका प्रदान करता है। इसका मतलब है कि धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार और जिम्मेदारियां हैं।

नागरिकता केवल अधिकारों का आनंद लेने के बारे में नहीं है। यह समाज में भाग लेने, दूसरों की सेवा करने और देश की प्रगति में योगदान करने के बारे में भी है। भारतीय मुसलमानों के लिए, इसका मतलब शिक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक सेवा, सार्वजनिक जीवन और सामुदायिक कल्याण में सक्रिय भूमिका निभाना है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिसमें समुदाय योगदान कर सकता है।

आज के भारत में, बेहतर रोजगार, आर्थिक अवसर और नेतृत्व के लिए शिक्षा आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक सोच, पेशेवर पाठ्यक्रम और तकनीकी कौशल पर अधिक जोर देने से युवाओं को बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिल सकती है। मुस्लिम समुदाय के शिक्षक, शोधकर्ता, विद्वान और पेशेवर भी भारत के बौद्धिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए, शिक्षा का समर्थन करने से न केवल व्यक्तियों और परिवारों को बल्कि पूरे समाज को लाभ होता है।

आर्थिक भागीदारी समान रूप से महत्वपूर्ण है। मुस्लिम उद्यमी, कारीगर, व्यापारी, पेशेवर और श्रमिक देश भर में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान करते हैं। उद्यमिता, नई तकनीक, नवाचार और आधुनिक कौशल के लिए अधिक समर्थन अधिक रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा कर सकता है। युवाओं को व्यापक अर्थव्यवस्था में योगदान देते हुए अपने समुदायों की सेवा करने वाले व्यवसायों और उद्यमों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। आर्थिक ताकत भी लोगों को सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में अधिक आत्मविश्वास से भाग लेने में सक्षम बनाती है। सामाजिक सेवा योगदान का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस्लामी शिक्षाओं में दान और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का एक मजबूत स्थान है, और कई व्यक्ति और संगठन पहले से ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याण में काम करते हैं। इस तरह के प्रयासों का अधिक प्रभाव हो सकता है जब वे सामुदायिक सीमाओं से परे लोगों तक पहुंचते हैं। छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, कौशल प्रशिक्षण और वंचित परिवारों के लिए सहायता समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विश्वास और सहयोग बनाने में मदद कर सकती है। समाज की सेवा तब अधिक सार्थक हो जाती है जब वह धार्मिक या सामाजिक मतभेदों के बजाय करुणा द्वारा निर्देशित होती है।

एक समावेशी भारत के लिए अपने विविध समुदायों के बीच अधिक बातचीत की आवश्यकता है। बहुलवाद केवल साथ-साथ रहने वाले विभिन्न समुदायों के बारे में नहीं है। इसका मतलब एक दूसरे के साथ संवाद करना, एक साथ काम करना और एक दूसरे से सीखना भी है। भारतीय मुसलमान लंबे समय से भारत के साझा सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। इस परंपरा को पड़ोस, स्कूलों, कार्यस्थलों और नागरिक संस्थानों में बातचीत और नियमित बातचीत के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। सामाजिक सद्भाव तब बढ़ता है जब लोग एक दूसरे को अलग-अलग समूहों के बजाय साथी नागरिकों के रूप में देखते हैं।

संविधान स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से इस साझा नागरिकता के लिए एक सामान्य आधार प्रदान करता है।

ये मूल्य रोजमर्रा के व्यवहार के माध्यम से सार्थक हो जाते हैं। दूसरों की गरिमा का सम्मान करना, कानून का पालन करना, पूर्वाग्रह को अस्वीकार करना और लोकतांत्रिक जीवन में रचनात्मक रूप से भाग लेना सभी नागरिकों द्वारा साझा की जाने वाली जिम्मेदारियां हैं। भारतीय मुसलमान, हर दूसरे समुदाय की तरह, नागरिक गतिविधियों में भाग लेकर, संवाद को प्रोत्साहित करके और युवाओं के बीच ज़िम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूत कर सकते हैं। डिजिटल युग ने नागरिकता में एक और आयाम जोड़ा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों के लिए संवाद करना और जानकारी का आदान-प्रदान करना आसान बना दिया है। साथ ही, झूठी जानकारी, रूढ़ियाँ और विभाजनकारी सामग्री तेजी से ऑनलाइन फैल सकती है। इसलिए सोशल मीडिया का ज़िम्मेदार उपयोग महत्वपूर्ण है। नागरिकों को इसे साझा करने से पहले जानकारी को सत्यापित करना चाहिए, अपमानजनक या भड़काऊ सामग्री से बचना चाहिए और सम्मानजनक चर्चा में शामिल होना चाहिए।

साझा नागरिकता का विचार अंततः एक सरल सिद्धांत पर निर्भर करता है: किसी भी समुदाय की प्रगति समग्र रूप से देश की प्रगति से निकटता से जुड़ी होती है। भारतीय मुसलमानों के पास एक समृद्ध विरासत है और भारत में योगदान का एक लंबा रिकॉर्ड है। शिक्षा, उद्यमिता, महिलाओं की भागीदारी, सामाजिक सेवा, सामुदायिक संबंधों और संवैधानिक मूल्यों पर अधिक ध्यान देकर, वे देश के भविष्य में और भी मजबूत योगदान दे सकते हैं।

यह भागीदारी समान नागरिकता की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। समावेशी भारत का निर्माण अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उन नागरिकों की आवश्यकता होती है जो समझते हैं कि उनकी अपनी प्रगति देश की प्रगति से जुड़ी है। लक्ष्य एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें विविधता का सम्मान किया जाए और प्रत्येक नागरिक के पास गरिमा, अवसर और भारत के साझा भविष्य में योगदान करने का उचित मौका हो।

कनाडा के रुख से भड़का ईरान

(वीपी राहुल-हिफी फीचर)

ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव एक बार फिर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने कनाडा पर अमेरिका के दबाव के आगे झुकने और वॉशिंगटन को खुश करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। तेहरान की यह नाराजगी कनाडा की उस नीति के बाद सामने आई है, जिसमें ओटावा ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को लेकर ईरान पर दबाव बनाए रखने और उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों की आलोचना की है।

कनाडा सरकार ने हाल ही में ईरान की गतिविधियों को अस्थिरता बढ़ाने वाला बताते हुए उसकी आलोचना की। कनाडा का कहना है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की ओर से दी जा रही धमकियां वैश्विक शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रही हैं। कनाडा ने यह भी कहा है कि वह अपने सहयोगी देशों, विशेष रूप से जी7 के साथ मिलकर ईरान पर दबाव बनाए रखना जारी रखेगा। ईरान ने कनाडा के इस रुख को स्वतंत्र विदेश नीति के बजाय अमेरिका के दबाव के आगे आत्मसमर्पण के रूप में देखा है। तेहरान का आरोप है कि कनाडा ने क्षेत्रीय परिस्थितियों को विकृत तरीके से पेश किया है और अमेरिका की रणनीति को मजबूत करने की कोशिश की है। ईरानी पक्ष के अनुसार, हॉर्मुज को लेकर किसी भी चर्चा में क्षेत्र की वास्तविक सुरक्षा परिस्थितियों और ईरान की संप्रभुता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इस पूरे विवाद को समझने के लिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व को समझना जरूरी है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित यह संकरा समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले तेल और गैस के बड़े हिस्से की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही इसी रास्ते से होती है। इसलिए यहां सैन्य तनाव या जहाजों की आवाजाही में किसी भी तरह की बाधा का असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। इसी वजह से पिछले कुछ समय से हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों की चिंता बढ़ाई है। हालिया घटनाक्रम में दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव फिर बढ़ा है और जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि उसके ठिकानों या हितों पर हमला जारी रहता है तो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ऊर्जा परिसंपत्तियां भी जोखिम में आ सकती हैं।

ईरान का रुख लगातार यही रहा है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उसकी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तेहरान ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका उसके खिलाफ सैन्य और आर्थिक दबाव जारी रखता है, तो वह जलडमरूमध्य में अपनी रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल जवाबी दबाव के लिए कर सकता है।

विचार

योगी की चुनाव तैयारी

(अशोक त्रिपाठी–हिफी फीचर)

पांच राज्यों के साथ 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसका एक कारण है 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का फीका प्रदर्शन और दूसरा कारण राम मंदिर चढ़ावा जैसे मामले हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ प्रदेश में हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव की बहुमुखी तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न नगरों के विकास की योजनाएं बन रही हैं और सभी वर्गों को साधने का प्रयास भी हो रहा है। इसी क्रम में योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय बढ़ाया और कैशलेस इलाज देने की सुविधा का ऐलान भी किया है। योगी सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक नई और विशेष रेंटल हाउसिंग नीति लाने का संकेत भी दिया है। गत दिनों यूपी के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े ने बूथ को मजबूत करने और सभी जातियों को साधे रहने का मंत्र दिया था। यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने एक आंतरिक सर्वे कराया है जिसके आधार पर 2027 में कई विधायकों के टिकट भी काटे जा सकते हैं।

इस प्रकार भाजपा यूपी में हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और योगी आदित्यनाथ की सरकार भी सभी वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए प्रयास कर रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार बुजुर्गों के लिए एक नई और विशेष रेंटल हाउसिंग नीति लाने की तैयारी कर रही है। इस नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और किफायती आवास उपलब्ध कराना है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने इसके लिए नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो नीति का प्रारूप तैयार कर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। प्रस्तावित योजना के तहत जरूरतमंद बुजुर्गों को कम किराये पर मकान उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। सरकार का मानना है कि वृद्धावस्था में किसी भी वरिष्ठ नागरिक को आवास के लिए भटकना न पड़े और उसे सुरक्षित रहने का विकल्प मिल सके।

इस प्रकार भाजपा यूपी में हैट्रिक लगाने को पूरी ताकत झोंक रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले एक-डेढ़ महीने में ही राज्य के ज्यादातर जिलों का दौरा कर विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी है। वर्ष 2022 की जीत की बात करें तो 1985 के बाद यूपी में यह पहला मौका था जब किसी मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी ने लगातार दूसरी बार पूरे बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। वहीं सपा-कांग्रेस गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित है। अखिलेश यादव जहां पीडीए के सामाजिक समीकरणों पर ध्यान केंद्रित किए हैं, वहीं कांग्रेस दलित-मुस्लिम वोटों को एकजुट करके अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी है। सन 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 255, अपना दल (सोनेलाल) को 12, निषाद पार्टी को 6 और एनडीए को 273 सीटें मिली थीं। प्रदेश में कुल सीटें 403 हैं और बहुमत 202 पर मिलता है।

उत्तर प्रदेश में मोदी-योगी लहर को कायम रखते हुए भाजपा को अकेले 41.29 प्रतिशत वोट मिले थे। भाजपा का पिछले चुनाव में अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी जैसे दलों के साथ गठबंधन रहा है। अब एनडीए के खेमे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल शामिल है। एनडीए का सपा-कांग्रेस गठबंधन से मुख्य मुकाबला होना तय है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, एआईएमआईएम जैसे दल भी ताल ठोकने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब छह महीने से भी कम वक्त बचा है। इस चुनाव में 10 साल से सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है। भाजपा ने स्थानीय विधायकों के कामकाज और लोकप्रियता का सर्वे कराते हुए जनता का मूड भांपने की कोशिश की है। माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से लगे झटके से सबक लेकर भाजपा ने 403 विधानसभा सीटों पर एक गोपनीय और बहुस्तरीय आंतरिक सर्वे कराया है।

इस सर्वे रिपोर्ट ने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी में करीब 125 से 128 मौजूदा विधायकों के खिलाफ उनके ही क्षेत्रों में जबर्दस्त एंटी इनकंबेंसी है। सीधे तौर पर कहें तो भाजपा में 128 सीटों पर मौजूदा विधायकों का टिकट काटा या बदला जा सकता है।

एक्शन इंडिया दैनिक

भगवान शंकर जी के ग्यारहवें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार-पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

आरएनआई: HPHIN / 2012 / 48072

एक्शन इंडिया मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक रवि भारद्वाज द्वारा एक्शन इंडिया कार्यालय, कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना हिमाचल प्रदेश–174303 से प्रकाशित एवं अर्थ प्रकाश प्रैस, अर्थ प्रकाश भवन, सेक्टर–29डी, चंडीगढ़ से मुद्रित।

संस्थापक : श्रद्धेय राकेश भारद्वाज जी
समूह संपादक : रवि भारद्वाज (9999889104)
स्थानीय संपादक : पंकज शर्मा (9418026789)
ई–मेल : actionindiashimla@gmail.com
actionindiauna@gmail.com

एक्शन इंडिया शिमला कार्यालय: किशोर भवन, जोधा निवास, डेजी बैंक एस्टेट, लोअर जाखू, शिमला– 171001
एक्शन इंडिया ऊना कार्यालय: कृष्णा टावर, सब्जी मंडी के सामने, ऊना, हिमाचल प्रदेश–174303

वैधानिक सूचना

पाठकों को सलाह है कि एक्शन इंडिया, समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के आधार पर कोई निर्णय लेने से पहले विज्ञापन में प्रकाशित उक्त उत्पाद या सेवा के बारे में आवश्यक जांच–पड़ताल कर लें। समाचार पत्र प्रबंधक किसी भी विज्ञापन में गुणवत्ता, सेवा आदि के विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता है। अत: समाचार पत्र उक्त विज्ञापनों के बारे में किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

आलेख

दिल्ली में छात्रावास हादसा

(वीपी राहुल-हिफी फीचर)

देश की राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में छात्रावास की इमारत ढहने से सात लोगों की मौत ने अवैध निर्माण, संपत्ति के लालच और भवन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे श्रमिक ठेकेदार सानोज को उत्तर प्रदेश के कासगंज से हिरासत में लिया और उसे दिल्ली लाया गया। पुलिस की जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि आखिर वह कौन-कौन सी परिस्थितियां थीं, जिनके कारण एक निमार्णाधीन इमारत अचानक ढह गई और सात लोगों की जान चली गई।

मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, भवन मालिक हरिराम गुप्ता और उनके भाई पर आरोप है कि उन्होंने अधिक किराया हासिल करने के उद्देश्य से पुराने भवन के ऊपर चार अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण कराया। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि पुरानी इमारत की नींव अतिरिक्त भार उठाने की स्थिति में नहीं थी। अगर जांच में यह आरोप सही साबित होता है तो यह केवल निर्माण संबंधी गलती नहीं होगी, बल्कि आर्थिक लाभ के लिए लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज करने का गंभीर मामला माना जाएगा। इस हादसे का सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि किसी भी बहुमंजिला इमारत में निर्माण या विस्तार से पहले उसकी संरचनात्मक क्षमता का आकलन किया जाना बेहद जरूरी होता है। पुरानी इमारत के ऊपर अतिरिक्त मंजिलें जोड़ने से उसका भार कई गुना बढ़ सकता है। ऐसे में नींव, बीम, कॉलम और भार वहन करने वाली दीवारों की तकनीकी जांच के बिना निर्माण करना गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। सत्य निकेतन की घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या इस तरह के निर्माण की निगरानी करने वाली व्यवस्था प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।पुलिस पूछताछ में महेश गुप्ता ने बताया कि उनके माता-पिता हरिराम और उर्मिला की ओर से वह आवास का प्रबंधन कर रहे थे। उसके अनुसार, अगस्त 2025 में इस इमारत को हॉस्टल डेज नाम के पीजी संचालक को पट्टे पर दिया गया था।

6जी की दौड़ में भारत की बड़ी छलांग

(वीपी राहुल-हिफी फीचर)

दुनिया अभी पूरी तरह 5जी की संभावनाओं का इस्तेमाल भी नहीं कर पाई है, लेकिन तकनीकी महाशक्तियों के बीच अगली पीढ़ी के 6जी नेटवर्क की तैयारी तेज हो चुकी है। इसी बदलती वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ उस अंतरराष्ट्रीय पहल में शामिल होने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के दूरसंचार नेटवर्क के विकास और दिशा को प्रभावित करना है। यह पहल केवल तेज इंटरनेट की दौड़ नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों की डिजिटल अर्थव्यवस्था, तकनीकी सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक शक्ति से जुड़ा बड़ा मुद्दा है।इस घटनाक्रम की जानकारी अमेरिकी वाणिज्य विभाग की ओर से दी गई। यह घोषणा उस समय हुई जब वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने जी20 नवाचार मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक से मुलाकात की। दोनों के बीच 6जी तकनीक के भविष्य पर चर्चा हुई। इसके बाद अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने कहा कि भारत अब अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के प्रयास का हिस्सा है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए विकसित हों, देशों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत करें और 6जी में नवाचार को बढ़ावा दें।

भारत के लिए इस पहल का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि दूरसंचार अब केवल संचार का माध्यम नहीं रह गया है। मोबाइल नेटवर्क से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त वाहन, रोबोटिक्स, रक्षा प्रणालियों, स्मार्ट शहरों, औद्योगिक स्वचालन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक, आने वाली अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अत्याधुनिक संचार ढांचे पर निर्भर करेगा। ऐसे में जिस देश के पास नेटवर्क की तकनीक, मानक और आपूर्ति श्रृंखला पर अधिक प्रभाव होगा, उसके पास भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी अधिक रणनीतिक ताकत होगी।

5जी ने मोबाइल इंटरनेट की गति और क्षमता को एक नई दिशा दी लेकिन 6जी का लक्ष्य केवल उससे अधिक तेज इंटरनेट उपलब्ध कराना नहीं माना जा रहा है।

'विकसित भारत 2047' के संकल्प को जनसंकल्प बनाएगा 'सेवा संकल्प अभियान' : मुख्यमंत्री

प्रस्तुतियां

☐ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री धर्मपाल की अभियान की तैयारियों की समीक्षा की

टीम एक्शन इंडिया

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल पूरा होने के अवसर को प्रदेश सरकार और प्रदेश संगठन मिलकर समारोहपूर्वक मनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलेगा। अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल की जनकल्याणकारी उपलब्धियों, नीतिगत सुधारों और देश-प्रदेश में आए बदलावों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल की उपस्थिति में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान व्यापक जनभागीदारी से हो और सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण तथा विकास की उपलब्धियों को वास्तविक लाभार्थियों की कहानियों के माध्यम से सामने लाया जाए। युवा, महिला, किसान और वंचित वर्ग सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को विकसित भारत के संकल्प का सहभागी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को जनपदों और अपनी-अपनी विधानसभाओं में जाकर तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय और जनपद स्तर पर त्रिस्तरीय समन्वय व्यवस्था बनाई गई है। केंद्र सरकार के 12 वर्षों और राज्य सरकार के 10 वर्षों के विकास कार्यों का डेटा-बैंक तैयार किया गया है। अभियान से 4.19 करोड़ परिवारों और 15.74 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, जिनमें 3.51 करोड़ ग्रामीण और 0.68 करोड़ शहरी परिवार शामिल हैं।

सेवा दिवस से शुरूआत : 17 सितंबर को सेवा दिवस

आशीर्वाद का दीया के तहत सेवा गतिविधियों के साथ शाम सात बजे दीप प्रज्वलन होगा। लाभार्थी परिवारों और प्रमुख विकास परियोजनाओं के स्थलों पर भी दीप जलाए जाएंगे। कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति होंगे। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती पर सभी विधानसभाओं में विश्वकर्मा पूजन और शिल्पकारों को टूलकिट वितरित किए जाएंगे।

मेरे सपनों का भारत : चित्र सेवाः 17 सितंबर से सात अक्टूबर तक विद्यालयों में चित्रकला और भाषण तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषण एवं डिबेट प्रतियोगिताएं होंगी। उत्कृष्ट प्रतिभाओं को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रभारी मंत्री संदीप सिंह को अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

नमो सेवा : अनकही कहानियां: सांस्कृतिक नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से 25 वर्षों की सेवा, जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास की कहानी गांव-गांव तथा शहरों तक पहुंचाई जाएगी। संस्कृति विभाग प्रत्येक जनपद में कलाकारों की टोलियां गठित करेगा। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह को प्रस्तुतियों की गुणवत्ता और स्थानीय प्रतिभाओं के सम्मान की व्यवस्था के निर्देश दिए गए।

आंगन मिलन सेवाः 25 सितंबर से सात अक्टूबर तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर तीन दिवसीय कार्यक्रम होंगे। कार्यकताओं, सहायिकाओं, आशा दीदियों और उत्कृष्ट लाभार्थी माताओं का सम्मान, हेल्दी बेबी प्रतियोगिता तथा पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां होंगी। प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य को माताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

न्यायमूर्ति अल्पेश कोगजे बने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

शपथ

☐ एक सादे समारोह में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

शपथ ग्रहण समारोह
2026
लोक भवन, मध्यप्रदेश

शपथ ग्रहण समारोह

टीम एक्शन इंडिया

भोपाल। न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने गुरुवार को यहां लोकभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित एक सादे समारोह में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने उनको शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री यादव ने शपथ ग्रहण के बाद नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश कोगजे को पुष्प-गुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे को नियुक्त किए जाने की अधिसूचना का वाचन किया। समारोह का प्रारंभ और समापन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् तथा राष्ट्रगान जन-गण-मन के गायन के साथ हुआ। शपथ ग्रहण के साथ ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को करीब तीन महीने बाद स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिल गया है। इससे पहले न्यायमूर्ति विवेक रुसिया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, उप मुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा और राजेन्द्र शुक्ल, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल, महापौर मालती राय, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, न्यायमूर्ति जी.एस. अहलूवालिया, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर, न्यायमूर्ति संदीप एन. भट्ट, न्यायमूर्ति विनय सराफ, न्यायमूर्ति रमेश फड़के, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह, अपर मुख्य सचिव डॉ. शिवशेखर शुक्ला और संजय शुक्ल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, विधायक, सांसद मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और आयोगों के पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति कोगजे इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम ने 31 अगस्त 2026 को उनके नाम की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने 5 सितंबर 2026 को अधिसूचित कर दिया था।

मुख्यमंत्री ने अपनी मां एवं तारापुर की पूर्व विधायक स्व0 पार्वती देवी जी की पुण्य तिथि पर किया नमन

स्मरणीय

☐ मातृशक्ति के रूप में उनका स्नेह, संस्कार और सेवा भावना सदैव स्मरणीय रहेगा: सीएम

टीम एक्शन इंडिया

भागलपुर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गुरुवार को को अपनी स्व माताजी एवं तारापुर की पूर्व विधायक पार्वती देवी की पुण्य तिथि पर मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड के तारापुर स्थित बीएड कॉलेज, पार्वती नगर पहुंचे और स्व पार्वती देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। उन्होंने अपनी मां को पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने अपनी मां को स्मरण करते हुए कहा कि मातृशक्ति के रूप में उनका स्नेह, संस्कार और सेवा भावना सदैव स्मरणीय रहेगा। स्व पार्वती देवी का जीवन और उनके दिए संस्कार आनेवाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। उनकी पुण्य स्मृतियां सदैव परिवारजनों और शुभचिंतकों के हृदय में जीवंत रहेंगी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी ने अपनी धर्मपत्नी स्व पार्वती देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी पार्वती देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पथ निर्माण मंत्री ई कुमार शैलेंद्र, विधायक कुमार प्रणय, विधायक ललित नारायण मंडल, विधायक मनीष कुमार, पूर्व विधायक राजीव कुमार सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, मुंगेर के आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राकेश कुमार, मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीकर, मुंगेर के पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद सहित अन्य वरीय अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन से लें प्रेरणाः मुख्यमंत्री धामी

नमन किया

☐ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनका स्मरण किया

टीम एक्शन इंडिया

देहरादून। आज प्रदेशभर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को उनकी जयंती पर याद किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनका स्मरण किया। उन्होंने कहा कि पंडित पंत हमारे लिए पाथेय हैं औउ उनके बताए रास्ते पर चलकर उत्तराखंड के विकास को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना ही भाजपा का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पंडित पंत प्रखर राजनीतिज्ञ के साथ ही सच्चे देशभक्त भी थे। उनका महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व हमारी युवा पीढ़ी के लिये सदैव प्रेरणादायी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पं. पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगारी प्रथा तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त इन बुराइयों को मिटाने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं देश के गृहमंत्री रहते आधुनिक भारत के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

पं. गोविन्द बल्लभ पंत का शानदार नेतृत्व देशवासियों के लिए सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। वहीं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती पर पिथौरागढ जिले में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशीष भटगांई, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों व स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

युवा केवल रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनेंः नितिन नवीन

SHREE NITIN NABIN with
YOUNG MINDS
September, 20
Hotel Ama

टीम एक्शन इंडिया

हल्द्वानी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं से राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आगे आने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बदलती अर्थव्यवस्था और तकनीक के दौर में युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। आज का युवा केवल रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि रोजगार और नए अवसरों का सृजन करने वाला भी बन रहा है। अध्यक्ष नितिन नवीन ने हल्द्वानी में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से करियर, रोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास, तकनीक, खेल और उत्तराखंड के भविष्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने रोजगार, स्वरोजगार और प्रदेश में बेहतर अवसरों से जुड़े सवाल पूछे तथा सरकार की योजनाओं को लेकर अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की युवा शक्ति को नई दिशा देने के साथ युवाओं के लिए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और खेलो इंडिया जैसी पहलों ने युवाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल के अनुरूप आगे बढ़ने का मंच दिया है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, नवाचार और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड के युवा प्रतिभा और क्षमता से भरपूर हैं तथा उनकी ऊर्जा को प्रदेश के विकास से जोड़कर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। अध्यक्ष नवीन ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर बढ़ाना महत्वपूर्ण है। युवाओं के विचार और आकांक्षाएं प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने युवाओं से भविष्य की चुनौतियों को अवसरों में बदलने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि यह एक सशक्त माध्यम है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी देशवासियों को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

हुगली में ममता की सभा पर कानूनी पेच, राज्य ने खंडपीठ का रुख किया

टीम एक्शन इंडिया

कोलकाता। हुगली के माहेश में तृणमूल कांग्रेस की प्रस्तावित सभा को लेकर कानूनी पेच अब कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ तक पहुंच गया है। एकल पीठ ने गुरुवार को शर्तों के साथ कालीघाट तृणमूल को सभा की अनुमति दी थी। इसके कुछ घंटे बाद राज्य सरकार ने आदेश के एक हिस्से को चुनौती देते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ का रुख किया। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कालीघाट तृणमूल को शुक्रवार को श्रीरामपुर के माहेश स्थित जगन्नाथ देव स्नानपिंड़ी मैदान में सभा करने की अनुमति दी है। सभा में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी शामिल होने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने सभा की अनुमति पर आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन मैदान के निजी संपत्ति होने को लेकर सवाल उठाया है। राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रविंद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ के समक्ष मामला उठाया।

दुर्गापूजा के स्टॉल पर 'शारदोत्सव' लिखने पर रोक, शुभेंदु ने

परंपरा

☐ सभी समुदायों के लोगों को धार्मिक विश्वास और परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए

टीम एक्शन इंडिया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गापूजा के दौरान लगाए जाने वाले स्टॉल और आयोजनों के नाम को लेकर कड़ा संदेश दिया है। गुरुवार को विधानसभा में उन्होंने कहा कि दुर्गापूजा के अवसर पर लगाए जाने वाले स्टॉल पर शारदोत्सव के बजाय दुर्गापूजा लिखा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुगार्पूजा की जगह दुर्गापूजा लिखे जाने वाले स्टॉल को अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गापूजा को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसके आयोजन में धार्मिक पहचान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान सभी समुदायों के लोगों को अपने धार्मिक विश्वास और परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन, कानून-व्यवस्था और धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में धार्मिक पहचान के आधार पर किसी विशेष समुदाय या समूह को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विरोध-प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है तो कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है।

नशे से दूर रहकर युवा अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाएं : राज्यपाल डेका

युवा शक्ति

☐ भारत युवाओं का देश है। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा पीढ़ी होती है

टीम एक्शन इंडिया

रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में नशा मुक्त युवाद्दविकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत विगत एक माह से आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आज गुरुवार को समापन हुआ। कार्यक्रम में कुलाधिपति एवं राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि, भारत युवाओं का देश है। किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा पीढ़ी होती है। युवा देश का भविष्य ही नहीं, बल्कि वर्तमान की भी महत्वपूर्ण शक्ति हैं। उनके विचार, संकल्प और सपने राष्ट्र की दिशा तय करते हैं। इसलिए युवा शक्ति को नशे जैसी बुराइयों से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2026 को युवाओं को नशामुक्त बनाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इस महाअभियान की शुरूआत की है। नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। आज पारंपरिक नशे के साथ सूखे नशे का चलन भी बढ़ रहा है, जो युवाओं के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है। राज्यपाल ने कहा कि, नशा व्यक्ति की सही और गलत में अंतर करने की क्षमता को प्रभावित करता है। नशे की गिरफ्त में आए व्यक्ति को दोषी मानने के बजाय उसके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए काउंसलिंग और आवश्यकता पड़ने पर उपचार उपलब्ध कराना चाहिए। अधिक नशे से मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। श्री डेका ने कहा कि, नशे से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जीवन में परीक्षा का दबाव, करियर की चिंता, असफलता का भय और अपेक्षाओं का बोझ जैसी परिस्थितियां आती रहती हैं। इनसे बचने के लिए नशे का सहारा लेना समाधान नहीं है। समस्या से भागना समाधान नहीं, बल्कि उसका सामना करना ही वास्तविक साहस है। उन्होंने युवाओं से अनुशासन, समय की पाबंदी और नियमित अध्ययन को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पढ़ने की आदत से ज्ञान के साथ-साथ विभिन्न विषयों के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। राज्यपाल ने डिजिटल एडिक्शन को भी गंभीर चुनौती बताते हुए युवाओं से डिजिटल माध्यमों का संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील की।

विकास की गति रहेगी निरंतर जारी, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति हमारी प्रतिबद्धताः गौर

टीम एक्शन इंडिया

भोपाल। मध्य प्रदेश की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि गोविन्दपुरा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन किया जा रहा है। क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक विकास और जन-कल्याण का यह प्रवाह अनवरत जारी रहेगा। राज्यमंत्री गौर गुरुवार को भोपाल के गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र में 70 लाख रुपये से अधिक के लागत के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं।

करमवीर नगर को मिली मंगल भवन की सौगात

राज्यमंत्री गौर ने वार्ड 66 करमवीर नगर में 25 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्थानीय नागरिक लंबे समय से एक सर्वसुविधायुक्त मंगल भवन की मांग कर रहे थे, जो आज पूर्ण हुई है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता, गांव में खोले जा रहे हैं सीबीएसई स्कूल: सीएम

समर्थन मूल्य

» दूध पर समर्थन मूल्य के रूप में इस वर्ष देंगे 200 करोड़ रुपये : सीएम

पंकज शर्मा

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज दैनिक समाचार पत्र हिमाचल दस्तक के 'नारी तू नारायणी' कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी दिशा में गांवों में सीबीएसई स्कूल खोले जा रहे हैं, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से दूध के खरीद मूल्य में वृद्धि की गई है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा गाय का दूध 61 रुपये और भैंस का दूध 71 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में करीब 200 करोड़ रुपये प्रदान करने जा रही है।

श्री सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा जिले के ढगवार में डेढ़ लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इस वर्ष अक्तूबर तक तैयार हो जाएगा। इससे किसानों और पशुपालकों की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाई जाने वाली गेहूं, मक्की और हल्दी जैसी फसलों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर स्तर पर नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हिमाचल प्रदेश, देश में 21वें स्थान पर था, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप प्रदेश अब पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।

सीबीएसई स्कूलों में 30 सितंबर, 2026 तक सभी अध्यापकों की होगी नियुक्ति

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 150 सीबीएसई स्कूल खोले हैं और 30 सितंबर, 2026 तक इन स्कूलों में सभी अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अध्यापकों का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। इन स्कूलों में भी मौजूदा फीस संरचना के अनुसार ही फीस ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को विदेशों में एक्सपोजर विजिट पर भेज रही है, ताकि वे दुनिया में हो रहे बेहतर कार्यों और आधुनिक व्यवस्थाओं को करीब से देख सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश का पहला साइंस कॉलेज करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जा रहा है।

एईडीपी विद्यार्थियों को उद्योग का अनुभव और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे : शिक्षा मंत्री

एमओयू

» अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के लिए बीओएटी-एनआर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम्स (एईडीपी) को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 16 राजकीय महाविद्यालयों में लागू करने के लिए प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने आज बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर (बीओएटी-एनआर) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की उपस्थिति में बीओएटी-एनआर के निदेशक विवेक कुमार तथा 16 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के मध्य हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को कम करना है। इसके तहत विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री के साथ-साथ वास्तविक कार्यस्थल का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष बल दे रही है।

उन्होंने कहा कि एईडीपी के तहत विद्यार्थी बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा, लॉजिस्टिक्स तथा रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट जैसे उद्योग-केंद्रित डिग्री कार्यक्रमों में अध्ययन करेंगे। इन कार्यक्रमों में शैक्षणिक अध्ययन के साथ उद्योग में कम से कम छह महीने की अनिवार्य प्रक्षिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) शामिल होगी।

विद्यार्थियों को प्रति माह न्यूनतम 10,900 रुपये का सुनिश्चित स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव प्राप्त करने और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा।

हिमाचल प्रदेश का पहला महिला संचालित मिनरल वाटर प्लांट हिमजल ठाणा में शुरू

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत विकास खंड चौपाल की ग्राम पंचायत ठाणा में हिमाचल प्रदेश का पहला महिला संचालित मिनरल वाटर प्लांट हिमजल शुरू किया गया है। इस प्लांट का संचालन एवं प्रबंधन महिला ग्राम संगठन ठाणा से जुड़ी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। यह पहल हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एचपीएसआरएलएम) के अंतर्गत की गई है।

उपमंडलाधिकारी (नागरिक), चौपाल, जंगवीर वन मंडलाधिकारी, चौपाल तथा सुशांत शर्मा उप पुलिस अधीक्षक, चौपाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी चौपाल विनीत ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा महिला ग्राम संगठन ठाणा की सदस्य महिलाएं उपस्थित रहीं।

परियोजना के लिए महिला ग्राम संगठन ठाणा को एचपीएसआरएलएम के माध्यम से 13.80 लाख रुपये की ऋण सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इस राशि से मिनरल वाटर प्लांट की स्थापना एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्लांट का संचालन, प्रबंधन, विपणन, पैकेजिंग तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां महिला ग्राम संगठन से जुड़ी महिलाओं द्वारा संचालित की जाएंगी।

इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी चौपाल विनीत ठाकुर ने कहा कि एचपीएसआरएलएम के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संगठनों को केवल बचत और ऋण गतिविधियों तक सीमित न रखते हुए उन्हें स्थायी, लाभकारी एवं बाजारोन्मुख ग्रामीण उद्यमों से जोड़ा जा रहा है।

चंबा में बढ़े बिजली-पानी के भारी-भरकम बिलों के खिलाफ चंबा जनहित संगठन का फूटा गुस्सा, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

हामिद खान

चंबा। चंबा जिला मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रों में जलशक्ति और बिजली विभाग द्वारा भेजे जा रहे भारी-भरकम बिलों को लेकर स्थानीय जनता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। %चंबा जनहित संगठन% ने इस संबंध में एक तीखा बयान जारी करते हुए राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन का आरोप है कि आम जनता, वरिष्ठ नागरिकों और मध्यम वर्ग का जीना मुहाल कर दिया गया है।

संगठन ने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि जिले में बिल भेजने की प्रक्रिया बेहद दोषपूर्ण है। एक वरिष्ठ नागरिक जो अकेले रहता है, उसे भी बाजार के कमर्शियल रेट के बराबर या भारी-भरकम बिल थमाए जा रहे हैं। दूसरी ओर, एक ही परिवार में कई किराएदार होने पर भी दो-दो कनेक्शन दर्शाकर लोगों से मनमाना पानी का शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे जनता मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है।

संगठन के अनुसार, चंबा जिला पहले से ही बिजली उत्पादन और पीने के पानी का रिजर्वॉयर होने के बावजूद यहां की जनता को महंगे बिलों और कई प्रकार के टैक्सों के बोझ तले दबाया जा रहा है। पानी के बिलों पर भी मीटर लगाने की शर्तें थोपी जा रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्कूल (सुक्खू) के गृह जिले में भी इस प्रकार के व्यापक विरोध के स्वर उठ चुके हैं।

चंबा जनहित संगठन ने आरोप लगाया है कि जब वे विपक्ष में थे, तब जनता की दिक्कतों को दूर करने के लिए बड़े-बड़े प्राण देते और आंदोलन करते थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद हालात जस के तस हैं। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि जहाँ चुनावी वादों में बिजली और पानी मुफ्त देने की बात कही जाती थी, वहीं आज 20-25 रुपए के बिलों की जगह हजारों रुपये के बिल जनता के घरों में पहुँच रहे हैं। महंगाई की मार झेल रही जनता इस वक्त पूरी तरह त्रस्त है।

संगठन ने चेताया है कि यदि व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं किया गया और बढ़े हुए बिलों से राहत नहीं दी गई, तो जनता का यह आक्रोश और तीव्र आंदोलन का रूप ले सकता है।

हस्तअक्षर कर्ताओं में जनहित संगठन के संयोजक डॉक्टर शादी लाल अपअधार किशोर के अलावा मेलाराम एलएस कलिया शिशुपाल अनिल कुमार विनोद कुमार राजेश कुमार मोहाएमएमेड खन साहित अन्य लोग शामिल रहे ।

संक्षिप्त खबरें

आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार का कोटा घटा, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के हिस्से का तेल-शक्कर बंद

हामिद खान

चंबा। हिमाचल प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले पोषण आहार में कटौती कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और तीन साल तक के बच्चों को मिलने वाले सरसों के तेल और शक्कर की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से रोक दी है।

विभाग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब केंद्रों में केवल 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के नियमित आने वाले बच्चों के लिए ही शक्कर और सरसों के तेल से भोजन पकाकर परोसा जाएगा।

इस अचानक हुए बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में नाराजगी है, क्योंकि कुछ समय पहले ही विभाग ने पोषण स्तर सुधारने के लिए सफेद चीनी की जगह देसी शक्कर देना शुरू किया था।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन ने स्पष्ट किया कि राशन की आपूर्ति सीधे निदेशालय स्तर से होती है। सामान की खेप न मिलने के कारण वे वितरण करने में असमर्थ हैं।

केंद्र पर राशन लेने आने वाली महिलाएं लगातार सवाल पूछ रही हैं कि अन्य खाद्य सामग्री के साथ तेल और शक्कर की कटौती क्यों की गई है, जिससे कार्यकर्ताओं पर अनावश्यक दबाव बन रहा है।

उधर अगर बाल विकास परियोजना के विभागीय पक्ष की बात की जाए तो उनका कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले राशन और पोषण सामग्री के मेन्यू में संशोधन निदेशालय और केंद्र सरकार के स्तर पर तय दिशा-निर्देशों के तहत किया गया है।

जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन आज यहां बचत भवन में निर्धारित प्रक्रिया के तहत शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। निर्वाचन प्रक्रिया उपायुक्त शिमला एवं पीठासीन अधिकारी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में संपन्न करवाई गई।

अध्यक्ष पद के लिए भूपेंद्र एवं सुरेंद्र रेटका, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए भरत सिंह कलांटा एवं मीनाक्षी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में भूपेंद्र को 13 मत, जबकि सुरेंद्र रेटका को 10 मत प्राप्त हुए। मतदान के दौरान दो मत अवैध घोषित किए गए। इस प्रकार भूपेंद्र को जिला परिषद शिमला का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में भरत सिंह कलांटा को 14 मत तथा मीनाक्षी को 10 मत प्राप्त हुए, जबकि एक मत अवैध घोषित किया गया। परिणामस्वरूप भरत सिंह कलांटा को जिला परिषद शिमला का उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया।

निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत उपायुक्त एवं पीठासीन अधिकारी अनुपम कश्यप ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष भूपेंद्र तथा उपाध्यक्ष भरत सिंह कलांटा को निर्धारित शपथ दिलाई।

मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा निगरानी को मिल रहा बढ़ावा : जितेंद्र सांजटा

टीम एक्शन इंडिया

शिमला। संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)-सह-निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन, हिमाचल प्रदेश जितेंद्र सांजटा, ह्रस् ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आम जनता को खाद्य मिलावट के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा पांच मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन संचालित की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में ये मोबाइल वैन शिमला, सोलन, कुल्लू, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में कार्यरत हैं। इन वैन के माध्यम से आम जनता, खाद्य कारोबार संचालकों तथा अन्य हितधारकों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मौके पर जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जितेंद्र सांजटा ने बताया कि मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी में खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मानकों की जांच की जाती है। इनमें टीपीसी मीटर एवं एसिड वैल्यू के माध्यम से खाद्य तेल की जांच, रिफ्रैक्टोमीटर से ज्ञस्स एवं शुगर की जांच, आयोडीन व स्टार्च की जांच तथा पानी की पीएच आधारित जांच प्रमुख हैं। इन जांचों के माध्यम से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा संभावित मिलावट संबंधी मामलों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एमएफटीएल पहल के माध्यम से प्रदेश में फील्ड स्तर पर सैंपलिंग और खाद्य पदार्थों की जांच में भी तेजी आई है। अब तक इन सुविधाओं के माध्यम से कुल 1,579 खाद्य नमूने एकत्रित किए गए हैं। इनमें बिलासपुर से 486, कुल्लू से 62, सिरमौर से 511 तथा सोलन से 520 नमूने शामिल हैं।

विकासात्मक योजनाओं के बजट का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करें: नेगी

टीम एक्शन इंडिया

रिकांगपिओ। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज रिकांग पीओ में लोक निर्माण विभाग मंडल कल्पा एवं करछम तथा जल शक्ति विभाग मंडल पूह एवं रिकांग पीओ के अधिकारियों के साथ विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संबंधित विभागों के माध्यम से संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान पेयजल योजना सुन्नम, नेसंग, लाबरंग, शुदारंग, निचार-छोत कंडा तथा तांगलिंग, सीवरेज योजना रिब्बा, नमज्ञा, सांगला, रारंग, बारंग, ख्वांगी एवं रिकांग पीओ तथा बहाव सिंचाई योजना रिब्बा, जंगी, लिप्पा, ठंगी, बोक्टु, कांचे पोंडा, चौरा, यूला एवं जानी की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त मल निकासी योजना कल्पा एवं पांगी, विभिन्न भवन निर्माण कार्यों, सड़कों तथा अन्य विकासात्मक कार्यों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। राजस्व मंत्री ने संबंधित विभागों से प्रत्येक विकासात्मक योजना में उपलब्ध अप्रयुक्त बजट का विस्तृत ब्यौरा मांगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं में बजट की राशि अभी तक खर्च नहीं हो पाई है, उस राशि को अन्य आवश्यक एवं पात्र कार्यों के लिए पुनर्विनियोजित करने के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए, ताकि उपलब्ध बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त बजट की भी समीक्षा की गई। राजस्व मंत्री ने संबंधित विभागों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के एवज में प्राप्त बजट का वर्षवार एवं मदवार विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से यह भी जानकारी मांगी कि आपदा से संबंधित कार्यों के लिए प्राप्त बजट में से कितनी राशि का उपयोग किया जा चुका है तथा कितनी राशि शेष है। साथ ही, यदि प्राकृतिक आपदा से संबंधित कार्यों के संबंध में कोई दायित्व शेष है तो उसका भी विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए, ताकि लंबित दायित्वों के निपटारे के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि किन्नौर जिला भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियों की दृष्टि से संवेदनशील है और यहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण समय-समय पर सड़क, पेयजल, सिंचाई तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने अधिकारियों को आपदा के बाद पुनर्बहाली के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा उपलब्ध धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डलझील में लंगर सेवा दे रहे पठानकोट के व्यक्ति की अचानक मौत

हामिद खान

चंबा। मणिमहेश यात्रा मार्ग पर स्थित डलझील में लंगर सेवा के दौरान एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान सुच्चा सिंह सैनी (51) पुत्र फकीर चंद, निवासी गांव तारागढ़ (पठानकोट) के रूप में हुई है। घटना का संभावित कारण हृदय गति रुकना माना जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सुच्चा सिंह पिछले कई दिनों से डलझील में लंगर समिति के साथ निष्काम सेवा दे रहे थे। बुधवार सुबह करीब 5 बजे वह अचानक बेसुध होकर गिर पड़े। साथ मौजूद लोगों ने इसे सामान्य चक्कर आना समझकर उन्हें होश में लाने के तमाम प्रयास किए, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर उनकी मौत की पुष्टि हुई। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई। दुर्गम इलाका होने के कारण राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन डीआर एफ) की सहायता से शव को सुरक्षित भरमौर पहुंचाया गया। इसके साथ ही पठानकोट स्थित परिजनों को घटना की सूचना दी गई, जो दोपहर बाद भरमौर पहुंच गए।

परिजनों की सहमति के बाद नागरिक अस्पताल भरमौर में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया गया।

मामले की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि डलझील में लंगर सेवा के दौरान एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट लग रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। पुलिस ने इस संबंध में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

13 साल बाद वापस मिला था शहीद पति का जॉर्ज क्रॉस, ब्रह्मी देवी की चतुर्वर्षी पर फिर याद आई संघर्ष की कहानी

कश्मीर ठाकुर

बिलासपुर। घुमारवीं क्षेत्र के भपराल गांव की ब्रह्मी देवी की जिंदगी संघर्ष, त्याग और अदम्य हौसले की ऐसी कहानी है, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनके पति नायक कृपा राम ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उनकी वीरता के सम्मान में उन्हें मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया था। यही मेडल बाद में चोरी हो गया और करीब 13 वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद वापस ब्रह्मी देवी तक पहुंचा।

नायक कृपा राम ब्रिटिश भारतीय सेना की 8वीं बटालियन, 13वीं फ्रंटियर फोर्स राइफल्स में तैनात थे। 12 सितंबर 1945 को सैन्य अभ्यास के दौरान एक राइफल ग्रेनेड उनके दस्ते के पास आ गिरा। साथियों की जान बचाने के लिए कृपा राम आगे बढ़े और ग्रेनेड को सुरक्षित स्थान पर फेंकने का प्रयास किया, लेकिन वह उनके हाथ में ही फट गया। इस अदम्य साहस में उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, जबकि उनके बलिदान से कई साथी सैनिकों की जान बच गई।

उस समय ब्रह्मी देवी की उम्र महज 13 वर्ष थी। वर्ष 1946 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने उन्हें उनके शहीद पति की ओर से जॉर्ज क्रॉस प्रदान किया था। बेहद कम उम्र में विधवा होने के बावजूद उन्होंने पति की इस आखिरी निशानी को पूरी जिंदगी संभालकर रखा।

वर्ष 2002 में उनके भपराल स्थित घर से यह मेडल चोरी हो गया। वर्ष 2009 में अचानक यह मेडल लंदन के प्रसिद्ध नीलामी घर की नीलामी सूची में सामने आया। इसके बाद हिमाचल पुलिस, भारत सरकार और ब्रिटिश अधिकारियों के स्तर पर कार्रवाई शुरू हुई और नीलामी रोक दी गई। लंदन में चली कानूनी लड़ाई में ब्रिटिश बैरिस्टर इयान मेस ने ब्रह्मी देवी का पक्ष बिना फीस यानी प्रो बोनो आधार पर रखा। अंतत: उनके हक को स्वीकार किया गया और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से मेडल वापस मिला।

11 मई 2015 को ब्रिटिश उच्चायोग के रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर ब्रायन मैककॉल भपराल गांव पहुंचे और समारोह में जॉर्ज क्रॉस ब्रह्मी देवी को वापस सौंपा। करीब 13 वर्ष बाद पति की वीरता की निशानी हाथ में पाकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए।

ब्रह्मी देवी के अंतिम वर्षों में उनकी देखभाल उनकी बहन के बेटे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने की। उन्होंने उनके जीवन और इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रह्मी देवी की चतुर्वर्षी पर उनकी संघर्षगाथा एक बार फिर स्मृतियों में जीवंत हो उठी है। संयोग से आज से एक दिन बाद 12 सितंबर को ही वर्ष 1945 में उनके पति नायक कृपा राम ने देश और अपने साथियों के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उनकी वीरता और ब्रह्मी देवी के वर्षों लंबे संघर्ष की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, त्याग और दृढ़ संकल्प की मिसाल है।